सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 03, अंक 213, नई दिल्ली, शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

अखंड सौभाग्य के पावन पर्व
करवा चौथ
की हार्दिक शुभकामनाएं।

03 दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे पर 240 किलोवॉट का पहला हाई-कैपेसिटी मेगाचार्जर लगाया

06 महिलाओं और बेटियां की कम या घटती संख्या

08 ओबीसी के हांथों विशेषकर 'यादवो' के हाथ होगी बिहार में सरकार बनाने की "मास्टर की"

ऑटो शाखा परिवहन विभाग दिल्ली माननीय सर्वोच्च न्यायालय और गृह मंत्रालय सचिव कमेटी के दिशा निर्देशों की कर रहा खुली अवहेलना, किसकी शय ?

संजय बाटला

दिल्ली भारत देश की राजधानी पर ना तो महिला सुरक्षित, ना आम जनता आखिर क्यों एक अनसुलझा सवाल।

दिल्ली परिवहन आयुक्त एक महिला, दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला फिर भी महिलाओं की सुरक्षा में कमी,

आप को यहां हम जिस बात से अवगत कराने जा रहे है यह बात आम जनता की जानकारी में हो सकता है शायद ना हो पर दिल्ली पुलिस, दिल्ली यातायात पुलिस, प्रवर्तन शाखा परिवहन विभाग, आटो शाखा के अधिकारी, विशेष परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त और जिला एवम् उच्च न्यायालय की जानकारी में अवश्य है।

सबसे मुख्य बात कि इस कारण से दिल्ली की सड़को पर ना सिर्फ जनता असुरक्षित हैं अपितु महिलाएं असुरक्षित हैं।

दिल्ली में अकेली महिला सबसे विश्वसनीय सार्वजनिक सवारी के रूप में आटो तीन पहिया तीन सवारी का प्रयोग करना पसंद करती है और यही एक बड़ा हादसे का शिकार बना सकता है।

इस हादसे और असुरक्षा करवाने के पीछे अगर कोई सच में जिम्मेदार है तो वह है आटो शाखा में कार्यरत बह अधिकारी जो पुराने वाहन को बदल कर नए वाहन का खरीदने के लिए आदेश /एलओआई जारी कर रहे हैं वो भी पूर्ण सत्यता की जांच किए बिना क्योंकि उसी कारण से दिल्ली में एक ही नंबर से कई आटो चलते पाए जाते हैं। अब जनता को कैसे पता की कौन सा आटो प्रमाणित है आटो शाखा परिवहन विभाग से और कौन सा अवैध।

अवैध आटो को चलाने वाले कितने निडर हैं इसकी जानकारी आप दिल्ली पुलिस स्टेशनो से पता कर सकते हैं क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ही समय पर एक ही नंबर के दो ऑटो पाए गए और जांच में दोनों के पास ही आटो को सड़क पर चलने के लिए अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध वह भी ओरिजनल पाए गए। एक ही नाम, एक ही नंबर और दस्तावेज भी मान्य। अब आप ही बताए की आटो शाखा के अधिकारी के बिना क्या यह संभव है ?

अब आपको बताते है इसके पीछे का एक और सचः- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में 1 लाख आटो के पंजीकरण के आदेश जारी किए हुए है जिसके आधार पर परिवहन विभाग नया आटो खरीदने के आदेश तभी जारी करता है जब पुराना आटो स्क्रैप हो जाता हैं। पिछले कुछ सालों से आटो स्क्रैप हुआ या नहीं की जानकारी अगर दिल्ली परिवहन विभाग के आटो शाखा के अधिकारी लेना चाहे तो उन्हें अपनी शाखा में बैठे बैठे ही आनलाइन जांच कर प्राप्त कर सकते हैं पर उनके पास जनता की सुरक्षा से ज्यादा जरुरी नए आटो को खरीदने का आदेश एलओआई जारी करना है जिस कारण वह जांच करना पसंद नहीं करते।

अब आपकी जानकारी हेतु बता दे आज से कुछ महीने पहले परिवहन विशेष के मुख्य सम्पादक स्वयं विशेष परिवहन आयुक्त विश्वेंदर से मिले थे और उन्हे सबूत उपलब्ध कराए थे की किस तरह आटो शाखा के अधिकारी बिन सत्यता की जांच किए पुराने

आटो के स्थान पर नए आटो खरीदने की एलओआई जारी कर रहे है और उन्होंने विश्वास दिलाया था की वह इसकी जाँच करवा कर गलता ढंग से एलओआई जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और आगे से स्क्रैप की जांच किए बिना एलओआई जारी नही होगी पर यह विश्वाश खोखला सिद्ध हुआ और आटो शाखा में एलओआई जारी करने वाले अधिकारी अब भी बिना पूर्ण सत्यता की जांच किए बेख़ौफ़ होकर एलओआई जारी कर रहे है।

आपकी जानकारी हेतु बता दें किसी भी मान्यता प्राप्त स्क्रैप डीलर को जब भी राज्य सरकार जहां से उसने अपना स्क्रैप यूनिट पंजीकृत करवाया है के पंजीकरण के बाद भी सड़क परिवहन एवम्-राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अपने स्क्रैप यूनिट को ऑपरेशनल का अप्रूवल लेना अनिवार्य है और ऑपरेशनल ही बिना वह स्क्रैप डीलर वाहन पोर्टल पर वाहन को जमा करने की सीओडी जारी तो कर पाता है पर वाहन को वाहन पोर्टल पर स्क्रैप नहीं दिखा पाता है और नॉन ऑपरेशनल स्क्रैप डीलरो की सीओडी पर ही आटो शाखा का अधिकारी वाहनों को खरीदने के आदेश जारी कर रहे है जिन मे ऐसे बहुत सी सीओडी हैं जहां वाहन मालिकों के पैन कॉर्ड नंबर ही नकली हैं और कई ऐसी हैं जिनमें बैंक का जो कोड दिखाया गया है वह भारत देश में मान्य नहीं हैं पर आटो शाखा के अधिकारी को या इस शिकायत को सबूतों के साथ पाने पर विशेष परिवहन आयुक्त को कोई फर्क नहीं क्योंकि अगर कोई हादसा होगा तो वह तो दिल्ली की सड़को पर चलने वाले नागरिक के साथ होगा उनके या उनके परिवार के साथ तो कम से कम नहीं।

अब अंतिम बात हरियाणा से पंजीकृत नान ऑपरेशनल स्क्रैप डीलर द्वारा उसका स्क्रैप लाइसेंस खत्म होने के बाद भी आटो के लिए सीओडी जारी की जा रही हैं और आटो शाखा के एलओआई जारी करने वाले अधिकारी का कहना है यह देखना हमारा नहीं स्क्रैप शाखा का काम है और उन्हें हमको सूचित करना होगा, यानी जानकारी के बाद भी एलओआई जारी करने का साहस,

ऐसे साहसी अधिकारियों के पद पर कार्यरत रहने और सबूत उपलब्ध कराने पर भी आयुक्त परिवहन एवम्-विशेष परिवहन आयुक्त द्वारा कार्यवाही नही करने से तो जरुर सुरक्षित रह पाएगी दिल्ली की सड़को पर चलने वाली अकेली महिलाएं एवं अन्य जनता।

"टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत" सेवा ही संकल्प है!

पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट

हमारा मकसद सिर्फ मदद नहीं, बदलाव लाना है।

A voice for the voiceless, and a hand for the helpless.

हमारा उद्देश्य है समाज के उन हिस्सों तक पहुँचना जो आज भी भूख, शिक्षा और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम जरूरतमंदों को बिना भेदभाव के भोजन, बच्चों को मुफ़्त शिक्षा, और समाज को जागरूकता देने का कार्य कर रहे हैं।

क्या मिलेगा हमसे जुड़कर

Ground-level food distribution,

Getting children free education,

हम मानते हैं – छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है।

If you believe in humanity, equality, and service — then you're already a part of our family.

हमें सपोर्ट करें और एक आवाज़ बनें इस बदलाव की।

Together, let's serve. Together, let's change.

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फार्म भरकर जुड़े,

www.tolwa.com/member.html

स्कैनर को स्कैन कर के भी आप टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से फार्म भर कर जुड़ सकते हैं,

वेब साइट पर www.tolwa.com पर भी जाकर आप फार्म भर के टोलवा ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। www.tolwa.com

SCAN ME

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत
tolwaindia@gmail.com
www.tolwa.com

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ द्वारा "डीटीसी बचाओ अभियान" चौथा दिन

बादली विधानसभा से विधायक श्री दीपक चौधरी जी

सीमापुरी विधानसभा से वीर सिंह धींगान जी

तेखंड विधानसभा से विधायक सही राम जी

पटपड़गंज विधानसभा से विधायक श्री रविंद्र नेगी जी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने "DTC बचाओ अभियान" की शुरुआत के चलते चौथे दिन इस भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, तथा DTC कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सभी मिलकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी के पास उनके निवास स्थान पर जाकर ज्ञापन दिया तथा दिल्ली की विधानसभाओं के विधायक

1. पटपड़गंज विधानसभा से लोकप्रिय विधायक श्री रवि नेगी जी

2. बदली विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री दीपक चौधरी जी

3. सीमा पुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री वीर सिंह धींगान जी 4. तेखंड विधानसभा से विधायक श्री सही राम जी

तक पहुंचें और उन्हें (DTC)दिल्ली परिवहन निगम की गंभीर समस्याओं से अवगत कराकर पत्र सौंपा1

यह अभियान दिल्ली के 70 विधायकों तथा 7 लोकसभा सांसदों को मांग पत्र सौंपे जाने तक चालू रहेगा, अभी तक दिल्ली के लगभग 15 विधायकों तक यह पत्र पहुंच चुके हैं पत्र को लेकर दिल्ली सरकार से DTC कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है कि जल्द उनको जॉब सिक्योरिटी और बेसिक DA ग्रेड PAY प्राप्त होगा तथा दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में दिल्ली सरकार की खुद की दिल्ली परिवहन निगम की बसें आयेंगी,

इस अभियान का तहत दिल्ली की जनता की जीवन रेखा डीटीसी बस सेवा को सशक्त बनाना,निगम के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना तथा दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना है1

भानु भास्कर जी द्वारा कहा गया कि दिल्ली सरकार में पूर्व में रही मुख्यमंत्री आतिशी जी ने यह सब सुविधा लागू कर दी थी परंतु वर्तमान में भाजपा सरकार यह सब लागू करने में अभी तक नाकाम रही है

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ प्रदेश कार्यालय अजमेरी गेट दिल्ली 110006

1. अध्यक्षः गूगन सिंह
2. महामंत्रीः भानु भास्कर

झारखंड में परिवहन अधिकारी/कर्मचारी मस्त, व्यवसायी त्रस्तः नेशनल परमिट गाड़ियों के साथ लूट आखिर कब तक?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्टर्स सारथी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने झारखंड के परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और व्यवसायियों के उत्पीड़न पर गहरा रोष व्यक्त किया है। डॉ. यादव ने कहा कि राज्य के परिवहन अधिकारी और स्वनिर्मित चेकपोस्ट पर तैनात कर्मचारी ट्रक मालिकों और ड्राइवरों से खुलेआम लूट मचा रहे हैं, विशेष रूप से नेशनल परमिट वाली गाड़ियों को निशाना बनाकर। यह स्थिति न केवल अर्थव्यवस्था को ठप कर रही है, बल्कि हजारों ट्रांसपोर्टरों को दिवालिया होने की कगार पर ला खड़ा कर रही है। ₹कब तक सहेंगे हम यह अन्याय? परिवहन अधिकारी मस्त हैं, लेकिन व्यवसायी त्रस्त हैं – यह लूट अब रुकनी ही चाहिए!" डॉ. यादव ने जोरदार शब्दों में कहा।

भ्रष्टाचार के चौंकाने वाले तथ्यात्मक आंकड़े

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, देशभर में ट्रक ड्राइवर और मालिक हर साल सड़कों पर लगभग 68,000 करोड़ रुपये की रिश्वत देते हैं, जिसमें झारखंड जैसे राज्यों का बड़ा हिस्सा शामिल है। इस राशि का लगभग 44% हिस्सा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (डीटीओ) अधिकारियों को जाता है, जहां नेशनल परमिट वाली गाड़ियों को बिना वजह रोककर जुर्माना या रिश्वत वसूली जाती है। एक अन्य रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 92% ट्रक ड्राइवरों ने अपनी पिछली यात्रा में किसी न किसी अधिकारी को रिश्वत दी है, और झारखंड में यह आंकड़ा और भी ऊंचा है,किन्तु मजाल है किसी बड़े व लिमिटेड कम्पनीयों के गाड़ियों को कभी रुकने का भी इशारा किया हो भला1 जहां चेकपोस्ट पर हर ट्रिप में औसतन 1,657 रुपये की वसूली होती है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2005 की रिपोर्ट में भी भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें गिनाते हुए कहा गया है कि सड़कों पर 60% रुकावटें केवल रिश्वत के लिए होती हैं, जिसमें पुलिस, वन विभाग, बिक्री कर और लीगल मेटलर्जी विभाग शामिल हैं झारखंड में 24 से अधिक डीटीओ कार्यालय हैं, जहां 6.5 मिलियन से ज्यादा पंजीकृत वाहनों के साथ यह समस्या और विकराल हो गई है। 2013 की एक सर्वे में 1,200 से अधिक ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि 60% मामलों में अधिकारी बिना वजह रोकते हैं और रिश्वत मांगते हैं, जिसमें पुलिस का हिस्सा 45% और डीटीओ का 43% है ।यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भ्रष्टाचार न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि निवेश को भी हतोत्साहित कर रहा है।

प्रमुख घटनाक्रम और उत्पीड़न की सच्ची कहानियां

झारखंड में यह समस्या नई नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में यह चरम पर पहुंच गई है। 2020 की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ट्रक ड्राइवरों को न केवल सरकारी अधिकारियों, बल्कि स्थानीय गुटों जैसे पूजा समितियों द्वारा भी लूटा जाता है, जहां 25% ड्राइवरों ने ऐसी वसूली की शिकायत की। हाल ही में, 2024 में महाराष्ट्र के जलगांव आरटीओ में एक अधिकारी को 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया, जो झारखंड जैसे राज्यों में भी समान पैटर्न दर्शाता है जहां नेशनल परमिट के नाम पर अनावश्यक जांच और जुर्माने लगाए जाते हैं। आज भी महाराष्ट्र की एक गाड़ी को सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर थाने मे गाड़ी वाले से परिवहन अधिकारी ने महाराष्ट्र का टैक्स फेल होने पर 120000/- रूपये की मांग की, गाड़ी मालिक व स्थानीय संगठन के वाक्यनुसार जो दयनीय, निंदनीय व दुःखद है1

एक प्रमुख घटना में, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2015 में सार्वजनिक रूप से कहा था कि ₹आरटीओ चंबल के डाकुओं से ज्यादा लूटते हैं,₹ और उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल की वकालत की। झारखंड में हाल के महीनों में कई ट्रक मालिकों ने शिकायत की है कि रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे क्षेत्रों में चेकपोस्ट पर नेशनल परमिट वाली गाड़ियों को घंटों रोका जाता है, और बिना रिश्वत दिए आगे नहीं जाने दिया जाता। एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि पुलिस (77%) और आरटीओ (73%) द्वारा उत्पीड़न सबसे ज्यादा है, जिससे अंतरराज्यीय सीमाओं पर 58% समय बर्बाद होता है। यह स्थिति न केवल ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है, बल्कि माल की आपूर्ति श्रृंखला को भी प्रभावित व धीमा कर रही है, जिससे महंगाई बढ़ रही है।

मांग और चेतावनी - डॉ. राजकुमार यादव ने मांग की है कि झारखंड सरकार तुरंत परिवहन विभाग में सुधार लाए,स्वस्थापित चेकपोस्ट पर नजर रखते हुए सीसीटीवी लगाए, और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ₹यदि यह लूट नहीं रुकी, तो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान करेगा,₹ उन्होंने चेतावनी दी। संगठन सभी ट्रांसपोर्टरों से अपील करता है कि वे एकजुट हों और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं।

क्या आप हिचकियों से परेशान रहते हैं

क्या आप हिचकियों से परेशान रहते हैं,
या फिर किसी को भी अचानक हिचकियाँ लग जायें तो....अपनायें ये देसी उपाय...
उपाय नम्बर 1..
नींबू... हिचकी को रोकने में नींबू बहुत लाभदायक होता है
यदि लगातार हिचकियां आ रही हों तो एक चम्मच ताज़ा नींबू का रस लें।
अब इसमें एक चम्मच शहद डालें।
दोनों को मिलाएं और चाट लें।
ऐसा करने से हिचकी बंद हो जाएगी।
उपाय नम्बर 2...
तीन काली मिर्च और थोडी सी धागे वाली मिश्री का एक टुकडा मुंह में रखकर चबायें
और उसका रस चूंसते रहे,
चाहे तो एक घूंट पानी पी सकते है,
तत्काल हिचकी बन्द हो जायेगी।
यह उपाय पूरी तरह सुरक्षित भी है।
उपाय नम्बर 3..
थोड़े से नमक को पानी में मिलाकर एक या दो घूंट पियें।
इससे हिचकी की समस्या में तुरंत आराम मिलेगा!
इसके साथ ही धीरे-धीरे सांस लें इससे आपको आराम मिलेगा।
आँवले का रस, पिप्पली या शहद के साथ लेने से हिचकी में फायदा होता है!

Viral Fever.. मौसमी बुखार.....

आजकल मौसमी बुखार (Viral Fever) फ़ैल रहा है। जो मौसम बदलने के कारण प्रत्येक वर्ष आता रहता है। इसका प्रभाव 5 से 7 दिन तक रहता है। घबराएँ नही।

लक्षण... खांसी, जुकाम, गला खराब होना, हरारत बुखार पैर खाली खाली लगना, सिर दर्द, बदन दर्द।

घरेलू नुस्खे.... 10 तुलसी के पते +2 लोंग+ 2 इलाइची+ 1 काली मिर्च + 20 mm कच्ची हल्दी का टुकडा + 2 इंच लम्बा दालचीनी का टुकडा इन सभी को पानी में उबाल कर काढ़ा बना लें। फिर गर्म - गर्म दिन में 3 बार पी सकते है।

गिलोय का काढ़ा..... गिलोय की बेल 1 फुट लेकर टुकड़े बना कर कूट ले और एक गिलास पानी में तब तक उबले जब वो आधा न रह जाए और ठंडा होने पर पी ले। या रोज 2 पत्ते धोकर खाएं।

सावधानी..... अगर आपको हाई बीपी या Piles है तो आप अदरक का सेवन न करें। छीकते समय नाक पर रुमाल रखें। साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आराम करें।

प्राकृतिक चिकित्सा..... रोगी के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखे और 2 से 3 मिनट में बदल दे।
पेट पर ठंडी पट्टी या मिट्टी पट्टी रखें 15 मिनट।
सामान्य आहार में
मौसमी फल , सलाद, अंकुरित खाए।
भीगी हुई मुन्नका का पानी पिएं।
नारियल पानी पिएं।
शहद में काली मिर्च डालकर दिन में 3 बार चांटे।
मुँह का स्वाद ठीक करने के लिए व ताकत के लिए रोज 15 से 20 किसमिस रात को भिगो कर रख दे और सुबह पानी को पी ले और किसमिस खा ले।
निम्बू की चाय पी सकते है।
अगर खांसी नही है तो ही मौसमी का जूस ले सकते है।

भगवान सिद्धिविनायक की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होने से उन्हें नवसाचा गणपति यानि मन्नत पूरी करने वाले गणपति कहा जाता है. ऐसी मान्यता है कि जहां कहीं भी दाईं ओर मूडी हुई हो उसे सिद्धि प्रदायक कहा जाता है। भगवान गणेश के मुख्य रूप से आठ स्वरूप माने जाते हैं. इन स्वरूपों में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है. अष्टविनायक स्वरूप में 'सिद्धि विनायक' सबसे ज्यादा मंगलकारी माने जाते हैं. सिद्धटेक नामक पर्वत पर इनका प्राकट्य होने के कारण इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है. यह भी माना जाता है कि इनकी सूंड सिद्दि की ओर है. इसलिए यह सिद्धि विनायक हैं. मात्र सिद्धि विनायक की उपासना से हर संकट और बाधा को नष्ट किया जा सकता है.

जहां कहीं भी दाईं ओर सूंड वाले भगवान गणेश की मूर्ति होती है, वो सिद्धपीठ कहलाता है।

जय सिद्धि विनायक

आत्मग्लानि' और 'अपराध बोध': क्या 78 साल बाद भी गटर में सिर्फ दलित ही उतरेगा?

गटर में घुसते दलित आदमी को मैला साफ करते देखा हैं मैने और मैने कई बार अपनी आँखें बंद की हैं ताकि आत्मग्लानि ना हो गिल्ट फील ना हो

नई दिल्ली, संजय साग़र सिंह। गटर में घुसते दलित आदमी को गटर से मैला साफ करते देखा है मैने और मैने कई बार अपनी आँखें बंद की है। बचकर निकलने की कोशिश की है ताकि आत्मग्लानि ना हो, गिल्ट फील ना हो, लेकिन अपराध बोध भला ऐसे कभी जाता है?

78 साल हो लिए हमने दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें कर ली तकनीक विकसित कर ली लेकिन गटर सफाई के लिए अभी भी मैला साफ़ करने गटर में सिर्फ़ दलित ही घुसेगा ये माइंड सेट नहीं बदल पाए।

पहले पिता, फ़िरि उसका बेटा, फिर बेटे का बेटा

हमे गटर में घुस कर सफाई करने बाले दलित सफाई सैनिक की कोई परवाह नहीं पर हम मायावती जी के हीरे के गहनों को देखदेख कर गदगद है। भगवान वाल्मीकि जयंती के जलूस में मेरे स्वर्गवाशी पिताजी उस समय अकेले व्यक्ति हुआ करते थे जो उनके प्रतिनिधियों को फूलों का हार पहनाते थे लेक़नि ज़ब कुछ लोग पीठ पीछे बोलते थे कि क्या मेल हमारा और उनका? वो सम्मान के लायक नहीं।

कोई भी समाज का ठेकेदार चाहे लाख ड्रामा करे ये सेक्युलरिज्म का हैं तो सारे हिंदू ही लेक़नि उस समय कोई नहीं आता था स्वागत करने कि ये हमारा फंक्शन नहीं दलित समाज का है।

लिखकर ले लो कुछ समाज के ठेकेदारों की मानसिकता अगले 100 साल भी नहीं बदलनी ऐसे कूड़ मगज है हम ! अंग्रेजो की रेलगाड़ी ने 50 साल की कमी पूरी कर दी, सबको एक ही डिब्बे में बिठाकर क्या स्वर्ण क्या दलित। 50 साल अभी भी पीछे थे फिर फ्लश टॉयलेट और सीवर सिस्टम ने 25 साल और कम कर दिए 25 साल अभी भी पीछे है लेक़नि दो पुराने बड़े नेता सौ साल पीछे कर गये थे हमे इस मामले में।

ये कमी भी तकनीक पूरा करेगी समाज के ठेकेदारों के बस की बात नहीं अब क्या करे उनकी सोच ही ऐसी है, जो कभी बदल ही नहीं सकती। मेरे लिए कोई जज दलित है, कुछ भी मायने नहीं रखता। मेरे लिए वो गटर वाला मायने रखता है, - जो मुझे राह चलते आहत करता है। तैजी से तरक्की करते भारत में मुझे उसकी हालत की फिकर है।

60 साल अपनी पहचान की राजनीति करने वाले इसे कभी समझ नहीं सकते। हां, जब मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धुलने का का किया था तब भी मैने कहा था कि इससे बेहतर होता कि देशभर के स्थानीय निकाय के लिए अनिवार्य किया जाय कि वे नाला साफ करने वाले लोगों को लांग बूट और दस्ताने उपलब्ध करायें।

और कुछ बदलाब भी हुए हैं वहीं, बंद न होना दुखद है लेक़नि इतना परिवर्तन जरूर दिखा कि अब बड़ी मैन रोडस पर सुपर सुकर मशीन दिखती हैं और छोटे रोड्स पर एक रस्सी वाली मशीन दिखती है, जो गटर के बाहर गंदगी निकाल कर ट्राली में गेर देती है। पर 100% जगह पर ये होना चाहिए क्योंकि मानव को गटर में घुसना पड़े ये बहुत ही अमानवीय है।

ज़ब मोदी दलितों को अपना सकते हैं तो - समाज में ये अपने अपने नियम वाले चन्द समाज के ठेकेदार इन कमजोर ग़रीब दलितों को क्यों नहीं अपना रहें हैं? आज़ भी यह सबसे बडा सवाल हैं???

आत्मग्लानि' और 'अपराध बोध': क्या 78 साल बाद भी गटर में सिर्फ दलित ही उतरेगा?????

कमज़ोरी और चक्कर आना हो सकता है खून की कमी का संकेत, ये देसी फूड्स तुरंत बढ़ाएंगे हीमोग्लोबिन

1. चुकंदर (Beetroot):
चुकंदर आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन C से भरपूर है। रोज इसका सलाद या जूस लेने से खून की कमी जल्दी दूर होती है।

2. अनार (Pomegranate):
अनार में आयरन, विटामिन A, C और E के साथ पोटेशियम भी होता है। यह खून को बढ़ाता है और कमजोरी दूर करता है।

3. गुड़ और तिल:
गुड़ में आयरन और तिल में कैल्शियम व अन्य मिनरल्स होते हैं। इनका लड्डू या मिश्रण खाएं।

4. हरी पत्तेदार सब्ज़ियां:
पालक, मेथी, सरसों, बथुआ आदि में भरपूर आयरन और फोलिक एसिड होता है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं।

5. सेब और खरबूजा:
सेब और खरबूजा में भी आयरन व विटामिन C मिलता है। इन्हें रोजाना खाने से फायदा होता है।

6. ड्राई फ्रूट्स:
खजूर, किशमिश, अंजीर व बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मददगार हैं।

7. दालें और अंकुरित अनाज:
मसूर, चना और मूंग जैसी दालें और स्प्राउट्स आयरन व प्रोटीन से भरपूर होते हैं।

प्रेम, विश्वास और अटूट बंधन का पर्व: करवा चौथ (10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत विशेष)

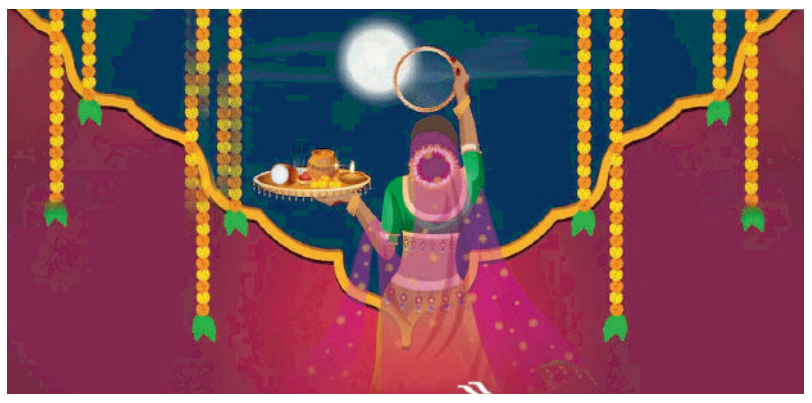

सनातन भारतीय संस्कृति में तीज-त्योहारों का प्रमुख व बड़ा स्थान है। कार्तिक का महीना इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठकों को बताता चलूं कि प्रतिवर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिनों द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने की पुरानी परंपरा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वर्ष यह व्रत 10 अक्टूबर 2025 यानी कि शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिनें अपने पति की सलामती और दीर्घायु होने की कामना के साथ दिन भर करवा चौथ का निर्जला उपवास रख माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार की आराधना करती हैं। करवा चौथ की कथा सुनतीं हैं। पाठकों को बताता चलूं कि करवा चौथ व्रत कथा मुख्यतः एक साहूकार की बेटी और उसके भाइयों की कहानी है, जो पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए व्रत रखती है। कथा के अनुसार, साहूकार की बेटी ने अपने भाइयों के कहने पर चंद्रमा के बजाय उनके द्वारा दिखाए गए अग्नि प्रकाश को चांद समझकर अर्घ्य दे दिया, जिससे उसका व्रत गलत तरीके से टूट गया। फलस्वरूप, उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। बेटी को जब अपनी गलती का अहसास हुआ तो उसने पूरे विधि-विधान से पुनः करवा चौथ का व्रत किया और चौथ माता से प्रार्थना की। उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर चौथ माता ने उसके पति को पुनः जीवनदान दिया और उसके घर में फिर से सुख-समृद्धि लौट आई। इस कथा के अनुसार, निष्ठा और सच्ची श्रद्धा से व्रत करने पर पति की आयु बढ़ती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा सत्यवान और सावित्री की करवा चौथ कथा भी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि जब मृत्यु के देवता यम, सत्यवान के प्राण लेने आए, तो सावित्री ने यम से उसे जीवनदान देने की विनती की। लेकिन यम अड़े रहे और उन्होंने देखा कि सावित्री ने खाना-पीना छोड़ दिया है और यम के पीछे-पीछे चल रही है, जब वे उसके पति को ले जा रहे थे। यम ने अब सावित्री से कहा कि वह अपने पति के जीवन के अलावा कोई भी वरदान मांग सकती है। सावित्री, एक बहुत ही चतुर स्त्री थी, उसने यम से संतान प्राप्ति का वरदान माँगा। और चूँकि वह एक समर्पित और निष्ठावान पत्नी थी, इसलिए वह किसी भी प्रकार के व्यभिचार की अनुमति नहीं देती थी। इस प्रकार, यम को सत्यवान को जीवन देना पड़ा ताकि सावित्री को संतान प्राप्त हो सके। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि यह पर्व(करवा चौथ) वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और आत्मीयता का उत्सव है, जो भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी के अटूट बंधन का प्रतीक माना जाता है।यह पर्व नारी के त्याग, समर्पण और सौभाग्य के भाव को उजागर करता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि परिवारिक जीवन केवल संबंधों पर नहीं, बल्कि आस्था, त्याग और विश्वास पर टिका होता है।'करवा' यानी मिट्टी का बर्तन (जल से भरा कलश) और 'चौथ' यानी चतुर्थी तिथि।इस दिन विवाहित महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, नई साड़ी या लहंगा पहन अपने रूप को निखारती हैं। कई महिलाएं शादी के बाद अपनी पहली करवा चौथ पर शादी का जोड़ा पहनती हैं।मान्यता के अनुसार, जब व्रती करवा चौथ के दिन शादी का जोड़ा पहनती है, तो अग्नि से पवित्र हुआ जोड़ा पूजा के फल को और बढ़ा देता है। इसके अलावा माना जाता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, खुशहाली आती है और संबंध मजबूत होते हैं।वास्तव में, इन दोनों के मेल से करवा चौथ का नाम पड़ा है। करवा 'स्थायित्व और समृद्धि' का प्रतीक माना जाता है।महाभारत काल से इस पर्व का जुड़ाव माना जाता है।ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी ने अर्जुन की सुरक्षा के लिए करवाचौथ व्रत रखा था, जब वे नीलगिरी पर्वत पर तप कर रहे थे। यह भी उल्लेखनीय है कि पहले जब पुरुष सीमाओं पर युद्ध करने जाते थे, तब उनकी पत्नियाँ उनकी रक्षा और दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत रखती थीं। बहुत कम लोग ही यह बात जानते होंगे कि किसी नवविवाहिता को पहली बार करवाचौथ व्रत उसकी सास या बहन ही करवाती है, इसे 'सौभाग्य आरंभ संस्कार' कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस व्रत का महत्व है, क्यों कि उपवास से शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है और मानसिक अनुशासन बढ़ता है। यह व्रत शरीर और मन दोनों को संयमित करने का प्रतीक भी है। महिलाएं ही नहीं कुछ स्थानों पर पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं ।पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में पति भी पत्नी के साथ व्रत रखते हैं, इसे 'समर्पण का प्रतीक' माना जाता है।पाठक जानते होंगे कि इस व्रत में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है और चंद्रोदय के पश्चात ही रात्रि के समय व्रत तोड़ा जाता है। वास्तव में, चंद्रमा को शीतलता, सौंदर्य और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। व्रत रखने वाली महिलाएं पहले चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करती हैं, तत्पश्चात छलनी से चंद्रमा के साथ पति का चेहरा निहारती हैं। जानकारी के अनुसार इस बार चतुर्थी तिथि का आगमन नौ अक्टूबर गुरुवार की रात 2.49 बजे हो रहा है, जो 10 अक्टूबर शुक्रवार की रात 12.24 बजे तक रहेगी। अंत में यही कहूंगा कि करवा चौथ अटूट वैवाहिक प्रेम और नारी समर्पण का प्रतीक है ।यह व्रत पति की दीर्घायु और मंगलकामना के लिए किया जाता है।इसमें नारी शक्ति, विश्वास और त्याग की झलक मिलती है ।चंद्रमा को साक्षी मानकर स्त्री अपने पति के प्रति श्रद्धा प्रकट करती है। यह पर्व भारतीय संस्कृति में दांपत्य जीवन की पवित्रता और अटूट बंधन का संदेश देता है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

विश्व दृष्टि दिवस केवल एक दिन नहीं, राष्ट्र निर्माण का आदर्श है

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह

व्यापक स्तर पर लोगों का ध्यान आंखों की समस्याओं, उनके कारणों और बचाव के उपायों की ओर जाता है। नेत्र जांच शिविर, जागरूकता अभियान, बच्चों व बुजुर्गों को लक्षित कार्यक्रम आयोजित होते हैं। लोगों को यह समझाया जाता है कि समय पर उपचार से अंधापन रोका जा सकता है।आधुनिक जीवनशैली, भागदौड़ और डिजिटल उपकरणों ने आज हमारे नेत्र स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला है। हर साल अक्टूबर का दूसरा गुरुवार हमें नेत्रस्वास्थ्य की अहमियत याद दिलाता है। कोई भी समाज जब नेत्रस्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है, तो न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार आता है, बल्कि विद्यार्थियों, श्रमिकों और वरिष्ठ जनों की जीवनशैली, उत्पादकता व आत्मसम्मान भी बढ़ता है।

आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं, जीवन की रंगत, शिक्षा की उन्नति, सामाजिक आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता की आधारशिला भी हैं। विश्व दृष्टि दिवस हम सबको जागरूक करता है कि यदि निवारण योग्य अंधता का समय पर उपचार हो जाए तो लाखों लोग उजाले की ओर लौट सकते हैं। बच्चों को अपनी आंखों से प्रेम करना, बुजुर्गों को समय पर नेत्र जांच कराना, युवाओं को स्क्रीन से आराम देना,ये छोटे-छोटे कदम समाज की दृष्टि को उज्ज्वल बना सकते हैं।

आज का दिवस हमें प्रेरित करता है कि अपने आस-पास के हर व्यक्ति को नेत्र स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाएं, सरकारी/गैरसरकारी नेत्र शिविरों में स्वयं पहल करें और नेत्रहीनों की मदद करके उनके सपनों में रंग भरने का काम करें। यदि हम नेत्र स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और जागरूकता फैलाएंगे, तो विकास की प्रत्येक सीढ़ी पर सफलता का उजाला हम सबके चेहरे पर दिखाई देगा।

विश्व दृष्टि दिवस केवल एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन आंखों के महत्व को पहचानने, बचाव के उपायों को अपनाने और समाज को जागरूक बनाने की आवश्यकता है। यही सच्ची नेत्र सेवा है और यही जागरूक राष्ट्र निर्माण का आदर्श है

आर. के. नारायण: साधारण पात्रों में असाधारण संवेदनाएँ

भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक दुनिया हर किसी की कल्पना में रंग-बिरंगे चित्रों से सजी होती है, पर जब बात आती है आम आदमी की सादगी, उसकी छोटी-छोटी उलझनों, उसकी हँसी और आँसुओं को संवेदनशीलता और मानवीयता के साथ उकेरने की, तो केवल कुछ ही लेखक इस शिखर तक पहुँच पाते हैं। उनमें से एक हैं आर. के. नारायण, जिन्होंने अपने साहित्य से भारतीय समाज की आत्मा को न केवल भारत में, बल्कि विश्व साहित्य के पटल पर अमर कर दिया। 10 अक्टूबर, 1906 को मद्रास प्रेसीडेंसी (वर्तमान तमिलनाडु) में जन्मे नारायण की रचनाएँ, खासकर मालगुडी डेज़ और उनके उपन्यास, महज कहानियाँ नहीं, बल्कि भारतीय जीवन की सूक्ष्म परतों और रोज़मर्रा की जटिलताओं का जीवंत चित्रण हैं। उनका काल्पनिक शहर मालगुडी एक ऐसी दुनिया है, जो भारतीय समाज के हर रंग को प्रतिबिंबित करता है—चाहे वह गलियों की चहल-पहल हो, स्कूलों की मासूम शरारतें हों, या आँगन की छोटी-छोटी बातचीत।

नारायण का साहित्य उस दौर के भारतीय समाज की उन बारीकियों को उजागर करता है, जो अक्सर भव्य ऐतिहासिक या राजनीतिक कथानकों में गुम हो जाती थीं। उनकी लेखनी की खूबी है आधुनिकता और परंपरा का ऐसा संतुलन, जो न केवल अपने समय में प्रासंगिक था, बल्कि आज भी उतना ही जीवंत और समकालीन लगता है। उनके पात्र—जैसे स्वामी, जो अपनी मासूम शरारतों से पाठक का दिल जीत लेता है, या राजम, जो अपनी निजी उलझनों में फँसकर भी जीवन की सादगी को दर्शाता है—सामान्य होते हुए भी असाधारण रूप से गहरे और सार्वभौमिक हैं। नारायण की कहानियों में हास्य और व्यंग्य इतने स्वाभाविक ढंग से गूंथे हैं कि पाठक मनोरंजन के साथ-साथ भारतीय समाज की गहरी सच्चाइयों से भी रू-ब-रू होता है। उनकी लेखनी में एक अनूठी संवेदनशीलता है, जो पाठक को पात्रों के साथ गहरा भावनात्मक रिश्ता जोड़ने को प्रेरित करती है।

मालगुडी डेज़ केवल कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि भारतीय समाज का एक जीवंत सांस्कृतिक और सामाजिक दर्पण है। इसकी कहानियाँ छोटे शहरों और गाँवों की ज़िंदगी को इतने प्रामाणिक और जीवंत ढंग से पेश करती हैं कि पाठक उस दौर में खो जाता है, जहाँ आधुनिकता की हल्की छुअन ने परंपरागत जीवन को बस छूना शुरू किया था। मालगुडी का हर कोना—रेलवे स्टेशन की भीड़, मंदिर की रौनक, या स्कूल की पाटियों पर बच्चों की शरारतें—जीवन की सादगी और जटिलता को एक साथ उजागर करता है। नारायण ने अपने पात्रों के माध्यम से भारतीय समाज की उन गहरी परतों को छुआ, जिन्हें शायद ही किसी लेखक ने इतनी सूक्ष्मता से चित्रित किया हो।

नारायण की लेखनी का सबसे अनूठा पहलू है उनकी भाषा की सरलता और प्रवाह। अंग्रेजी में लिखने के बावजूद, उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं की गहरी छाप है। यह उनकी कला का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनकी अंग्रेजी रचनाएँ भारतीय जीवन की आत्मा को बिना किसी बनावटीपन के व्यक्त करती हैं। उनकी शैली में स्वाभाविक हास्य और व्यंग्य है, जो सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं पर हल्का-सा कटाक्ष करता है। उदाहरण के लिए, उनके उपन्यास द गाइड में, राजू का किरदार एक साधारण गाइड से आध्यात्मिक गुरु तक का सफर तय करता है, जो भारतीय समाज में आध्यात्मिकता और विश्वास की जटिलताओं को उजागर करता है।

आर. के. नारायण ने अपने साहित्य में भारतीय जीवन की उन सूक्ष्म परतों को उजागर किया, जो औपनिवेशिक और पश्चिमी नजरियों में अक्सर अनदेखी रह जाती थीं। उनके उपन्यास और कहानियाँ छोटे शहरों के सामाजिक ताने-बाने, पारिवारिक रिश्तों, परंपराओं, और व्यापारिक-शैक्षिक संस्थानों को इतने जीवंत और प्रामाणिक ढंग से चित्रित करती हैं कि वे न केवल साहित्यिक कृतियाँ हैं, बल्कि बीसवीं सदी के मध्य भारत का एक सामाजिक-सांस्कृतिक दस्तावेज भी हैं। उनका काल्पनिक शहर मालगुडी उस दौर के भारत की एक ऐसी जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो महानगरों की चकाचौंध और औपनिवेशिक प्रभावों से अछूता था। मालगुडी की गलियाँ, बाज़ार, स्कूल, और मंदिर न केवल कहानियों का मंच हैं, बल्कि भारतीय जीवन की सादगी में छिपी असाधारणता का प्रतीक हैं। ये कहानियाँ आज के वैश्वीकरण और शहरीकरण के दौर में और भी प्रासंगिक हो उठती हैं, क्योंकि ये हमें उस सादगी की याद दिलाती हैं, जो आधुनिकता की दौड़ में कहीं खो गई है।

नारायण ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्होंने साबित किया कि अंग्रेजी भाषा न केवल पश्चिमी विचारों का माध्यम है, बल्कि भारतीय संस्कृति, संवेदनाओं, और जीवन-दर्शन को विश्व मंच तक पहुँचाने का भी सशक्त जरिया हो सकती है। उनकी रचनाओं ने न केवल भारत में, बल्कि विश्व भर में ख्याति अर्जित की। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों के साथ उनकी रचनाएँ कई भाषाओं में अनुवादित हुईं। मालगुडी डेज़ को टेलीविजन धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने उनकी कहानियों को एक नई पीढ़ी तक पहुँचाया, और इस तरह उनके साहित्य ने समय और पीढ़ियों की सीमाओं को लाँघा।

नारायण का योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं है; उन्होंने उन भारतीय कहानियों को आवाज़ दी, जो बड़े मंचों पर शायद ही कभी सुनी जाती थीं। उनके साहित्य में छोटे शहरों और गाँवों की ज़िंदगी, वहाँ के लोगों की आकांक्षाएँ, उनकी छोटी-छोटी खुशियाँ और दुख इतने जीवंत और प्रामाणिक ढंग से उकेरे गए हैं कि वे आज भी उतने ही जीवंत और प्रासंगिक हैं। उनकी रचनाएँ हमें सिखाती हैं कि साहित्य का असली उद्देश्य है जीवन की सादगी में छिपे गहरे अर्थों को उजागर करना, और यही नारायण की लेखनी की अमरता का रहस्य है। उनकी कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें अपने समाज, अपनी संस्कृति, और स्वयं के भीतर झाँकने का एक अनमोल अवसर प्रदान करती हैं।

आर. के. नारायण न केवल एक लेखक थे, बल्कि भारतीय समाज के गहन पर्यवेक्षक, मानवीय संवेदनाओं के कुशल चितेरे, और भारतीय जीवन के अमर दस्तावेज़ के रचनाकार थे। उनकी जयंती हमें उनके साहित्य की कालजयी विरासत को याद करने का अवसर देती है, साथ ही उन अनकही कहानियों की ओर ले जाती है, जो आज भी हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की नींव हैं। उनकी लेखनी की गहराई, सहज सरलता, और गहन मानवता न केवल भारतीय साहित्य, बल्कि विश्व साहित्य में उन्हें एक अद्वितीय स्थान प्रदान करती है। नारायण की रचनाएँ एक ऐसी जादुई दुनिया रचती हैं, जो पाठक को भारतीय जीवन की सादगी, जटिलता, और सुंदरता से जोड़ती है, और यही उनकी अमरता का रहस्य है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

व्यंग्य : चोरी चिन्तन !

कस्तूरी दिनेश

रावणभाठा का यशस्वी चोर पालू मल्हार, चोरी को महान कला और खुद को एक उम्दा कलाकार बताता है ! उसने आज तक रेकार्ड डेढ़ हजार चोरी की परन्तु बहुतायत नेताओं की तरह आज तक कभी पकड़ा नहीं गया ! यहाँ तक कि उसने कई बार पुलिस को चैलेन्ज करके चोरी की और पुलिस बेचारी टापती ही रह गई ! अद्भुत चोर है वह ! उसने अपनी कला को देश के महान नेताओं के प्रतिष्ठित चौर्यकला के स्तर तक पहुंचाया ! शहर और शहर के बाहर बड़े-बड़े व्यापारी भी उससे डरते हैं और सलाम ठोकते हैं ताकि पालू की कृपा-दृष्टि उनके घर पर न पड़े ! किंवदंती है कि उसकी कला के जादू से पुलिसिया डिपार्टमेंट भी नहीं छूटा !

पालू के बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि वह बेहद बातूनी है ! एक दिन उससे मेरी मुलाक़ात हुई ! उसकी प्रसिद्धि से मैं भयभीत था । उसे देखते ही अनायास मेरे दोनों हाथ अभिवादन में स्वस्फूर्त जुड़ गए। मन में यही भाव था कि हे करुणावतार पालू देव, अपनी कृपा से मेरे घर को बचाए रखना ! वह मुस्कुराया । उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच का भाव था । उसने कहा—"सर जी मुझे हाथ जोडकर क्यों शर्मिंदा करते हैं.... ? आप पत्रकार हैं,विद्वान हैं ! कहाँ आप,कहाँ मैं !"

मैं उसकी विनम्रता से थोड़ा सहज हुआ और मुस्कुराते हुए बोला—"पालू भाई, मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए...।" वह हंसते हुए बोला—"बड़े-बड़े नेता,अफसर कलाकार, साहित्यकार को छोडकर मेरा इंटरव्यू...? क्यों मजाक करते हैं सर जी...?" मैंने कहा—"नहीं पालू भाई मैं मजाक नही कर रहा,मुझे आपका ही इन्टरव्यू चाहिए...!" वहां पड़े एक खाली बेंच की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा—"आइये यहाँ बैठकर बात करते हैं...।"

हम इत्मीनान से वहाँ बैठ गये । मैंने कहा-"आप बेधड़क अपनी बात कहिये । मैं उसमें से अपनी काम की चीज निकाल लूंगा...! वह अपना घुटा हुआ सर खुजलाया और मुस्कुराते हुए बोला—"सर जी, मेरे मत से दूसरी कलाओं में कुछ न कुछ अपूर्णता है पर मैं चोरी को एक पूर्ण-कला मानता हूँ...! चौर्य-कला में एक निपुण चोर को एक्टर तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका मेकअप - आर्टिस्ट होना बेसिक आवश्यकता है । एथलीट का गुण हो तो सोने में सुहागा ! विभिन्न पशु-पक्षियों की आवाज की नकल का हुनर उसकी कला में चार चाँद लगा देती है ! कुश्ती-कराटे का दाँव-पेंच भी आना ही चाहिए...!" वैसे मैं तो एक छोटा चोर हूँ...! यहाँ हमारे देश में तो एक से एक महान यशस्वी चोर भरे हुए हैं ! चोरी भी कई प्रकार की होती है सर जी...! साधारण चोर धन-असबाब की चोरी करता है , व्यापारी टैक्स की चोरी करता है, नेता जनता के माल को उड़ा देते हैं । सरकारी मुलाजिम का चेहरा बिना कमीशन खाए बेशरम के फूल की तरह मुरझा जाता है !आज अखबार पढ़ रहा था तो पता चला कि हमारे प्रजातंत्र में तो आजकल वोटों की भी चोरी होने लगी है...! आपको एक मजेदार बात बताऊं, कल मेरा एक चोर दोस्त किसी घर में चोरी करने घुसा !कमरे में एक ओर लाखों के गहने से भरी तिजोरी खुली पड़ी थी. बाजू में एक सुंदर सी युवती सो रही थी । वह चोरी करना छोड़ मुग्ध-भाव से उसे एकटक देखता रहा और बिना चोरी किये चला आया ! मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, क्या चोरी करता भाऊ, उस लड़की ने तो मेरा दिल ही चुरा लिया...!

अपने देश में तो कुआँ-तालाब, खेत-खलिहान तक की चोरी आम है...! आप मानेंगे नहीं, चोरी सिर्फ स्थानीय,प्रांतीय या राष्ट्रीय ही नहीं होती, अन्तरराष्ट्रीय भी होती है ! आपको तो मुझसे ज्यादा पता है कि अंग्रेज भारत से अरबों-खरबों का माल सफाई से चुराकर कैसे ले गये ...! हमारे जनप्रतिनिधि आजकल जेब में संविधान लेकर चलते हैं ,मुझे तो डर लग रहा है किसी दिन कोई चोर उनकी जेब से संविधान ही उड़ाकर न ले जाए...!"

तभी उसका एक दोस्त बाइक पर आया और उसे इशारे से बुलाने लगा । पालू उठता हुआ बोला—"सर जी,सॉरी...एक मिनट...! वह अपने दोस्त से मिलने चला गया । उनमें कुछ देर गुफ्तगू होती रही फिर वह मेरी तरफ लौटकर आया और कहने लगा—"सर जी माफी..एक जगह बहुत जरुरी रेकी करने जाना है...! फिर मिलता हूँ न आप से...!"

कंक्रीट से हरियाली तक: शहरी खेती की नई कहानी

भारत के शहरी परिदृश्य में, जहाँ कंक्रीट की ऊँची इमारतें आकाश को छूती हैं, हरियाली की लहरें जोर पकड़ रही हैं। प्रदूषण की धुंध और ट्रैफिक के शोर के बीच, ताजा फल-सब्जियों की सुगंध शहरों को नई जिंदगी दे रही है। यह शहरी भारत में हरित क्रांति 2.0 की जीवंत हकीकत है। ऊर्ध्वाधर खेती और स्मार्ट कृषि के बल पर, शहर अब केवल उपभोग के केंद्र नहीं, बल्कि खाद्य उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और नवाचार के गढ़ बन रहे हैं। यह क्रांति खाद्य संकट का समाधान होने के साथ-साथ शहरी जीवन को हरित, स्वस्थ और टिकाऊ बनाने का दृढ़ संकल्प है।

पारंपरिक खेती अब अपने अंतिम चरण में है। बढ़ती जनसंख्या, जो 2030 तक 1.5 अरब तक पहुँच सकती है, ने कृषि योग्य भूमि पर भारी दबाव डाला है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 1970 के 0.34 हेक्टेयर से घटकर 2020 में केवल 0.12 हेक्टेयर रह गई है। जल की कमी, मिट्टी की उर्वरता में ह्रास और लंबी आपूर्ति श्रृंखलाओं से होने वाला खाद्य नुकसान इस समस्या को और जटिल बनाता है। लेकिन ऊर्ध्वाधर खेती और स्मार्ट कृषि ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया है। ये तकनीकें खाद्य उत्पादन को शहरों के निकट लाती हैं और न्यूनतम संसाधनों के साथ अधिकतम उपज सुनिश्चित करती हैं।

ऊर्ध्वाधर खेती, अर्थात्‌ वर्टिकल फार्मिंग, शहरों की सीमित जगह को हरित खेतों में परिवर्तित कर रही है। पुरानी इमारतों की छतें, खाली गोदाम और गगनचुंबी इमारतों की दीवारें अब फसलों का आश्रय बन रही हैं। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स जैसी तकनीकों ने खेती को मिट्टी और विशाल खेतों की आवश्यकता से मुक्त कर दिया है। एक छोटी छत पर सैकड़ों किलो साग-सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं, जो पारंपरिक खेती की तुलना में 10 गुना अधिक उपज देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण, ये तकनीकें 70-90% पानी बचाती हैं, जो भारत जैसे जल-संकटग्रस्त देश के लिए क्रांतिकारी है। नियंत्रित वातावरण में कीटों और रोगों का खतरा लगभग नगण्य है, जिससे जैविक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन शहरवासियों की थाली तक पहुँचता है।

स्मार्ट कृषि इस क्रांति का दूसरा सशक्त आधार है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ड्रोन और सेंसर के उपयोग ने खेती को डेटा-आधारित बना दिया है। मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों की स्थिति और फसल की वृद्धि की जानकारी अब तत्काल उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, बैंगलोर की स्टार्टअप क्रॉपटेक ने स्मार्ट सेंसर और एआई के माध्यम से शहरी किसानों को उनकी फसलों की देखभाल के लिए सटीक मार्गदर्शन प्रदान किया है, जिससे उपज में 20-30% की वृद्धि हुई है। ड्रोन कीट प्रबंधन और फसल निगरानी में सहायता करते हैं, जबकि स्वचालित सिंचाई प्रणालियाँ पानी और ऊर्जा की बचत करती हैं। यह तकनीक न केवल उत्पादन को बढ़ाती है, बल्कि खेती को पर्यावरण के लिए अधिक टिकाऊ बनाती है।

इस क्रांति का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव अत्यंत गहरा है। शहरी खेती ने युवाओं के लिए रोजगार के नवीन अवसर खोले हैं। तकनीकी विशेषज्ञ, डेटा विश्लेषक और शहरी किसान जैसे नए व्यवसाय उभर रहे हैं। मुंबई की अर्बन-खेती जैसी पहल ने सिद्ध किया कि छतों पर हाइड्रोपोनिक्स से न केवल ताजा सलाद और सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं, बल्कि स्थानीय रेस्तरां और घरों तक उनकी आपूर्ति से खाद्य अपव्यय भी कम होता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 40% खाद्य पदार्थ बर्बाद होता है, मुख्य रूप से लंबी आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण। शहरी खेती इस समस्या को मूल से समाप्त करने की क्षमता रखती है। साथ ही, छतों पर बगीचे और सामुदायिक खेती ने शहरी निवासियों को प्रकृति से जोड़ा है, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता में वृद्धि हो रही है।

पर्यावरण की दृष्टि से, यह क्रांति शहरों को साँस लेने योग्य बना रही है। हरित छतें और ऊर्ध्वाधर ग्रीनहाउस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और शहरी तापमान को 3-5 डिग्री सेल्सियस तक कम करते हैं। स्थानीय उत्पादन से परिवहन की आवश्यकता घटती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। इसके अतिरिक्त, ये हरित संरचनाएँ पक्षियों और कीटों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिससे शहरी जैव विविधता को प्रोत्साहन मिलता है। दिल्ली मेट्रो ने अपनी कुछ इमारतों पर छतों पर बगीचे शुरू किए हैं, जो न केवल खाद्य उत्पादन में योगदान दे रहे हैं, बल्कि शहर की हवा को भी स्वच्छ बना रहे हैं।

हालाँकि, इस मार्ग में चुनौतियाँ भी हैं। ऊर्ध्वाधर खेती और स्मार्ट कृषि में प्रारंभिक निवेश अधिक है। हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम, सेंसर और बिजली की खपत लागत को बढ़ाते हैं। साथ ही, तकनीकी ज्ञान की कमी भी एक रुकावट है। फिर भी, ये चुनौतियाँ असाध्य नहीं हैं। सरकार द्वारा सब्सिडी, कम ब्याज दरों पर ऋण और प्रशिक्षण कार्यक्रम इस क्रांति को गति प्रदान कर सकते हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी, जैसे बैंगलोर की ग्रोइंग ग्रीन्स जैसी स्टार्टअप, शहरी खेती को किफायती और विस्तार योग्य बना रही हैं। सामुदायिक खेती मॉडल भी लागत साझा करने का एक प्रभावी तरीका है। भारत के शहर इस दिशा में पहले ही कदम उठा चुके हैं। मुंबई में लेट्सेट्रा एग्रीटेक ने छोटे पैमाने पर हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से साग-सब्जियाँ उगाकर स्थानीय बाजारों को आपूर्ति शुरू की है। बैंगलोर में रूफटॉप फार्म्स ने स्मार्ट तकनीकों के साथ शहरी खेती को नया आयाम दिया है। ये उदाहरण प्रमाणित करते हैं कि सीमित संसाधनों में भी उच्च गुणवत्ता और उत्पादन संभव है।

यह हरित क्रांति 2.0 केवल खेती की तकनीक नहीं, बल्कि एक सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन है। यह हमें सिखाती है कि विकास और प्रकृति में संतुलन संभव है। यह शहरों को न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें हरित, स्वस्थ और टिकाऊ बनाती है। यदि हम आज इस दिशा में कदम उठाएँ, तो कल का भारत न केवल भोजन की मेजों पर हरा-भरा होगा, बल्कि उसका पर्यावरण भी स्वच्छ और जीवंत होगा इस क्रांति को गले लगाएँ। जहाँ इमारतें आकाश को छूती हैं, वहाँ फसलें भी ऊँचाइयों को छू सकती हैं। जहाँ तकनीक और सपने एकजुट होते हैं, वहाँ शहरी भारत में हरित क्रांति का सूरज उदय होता है। यह समय है परिवर्तन का, ताकि हमारा भविष्य हरियाली, ताजगी और समृद्धि से परिपूर्ण हो।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

बचत उत्सव के निहितार्थ

डॉ.वेदप्रकाश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरंभ से ही विजन और मिशन के तहत काम कर रहे हैं। यह भी स्पष्ट है कि उनके विजन और मिशन के केंद्र में आम जन, भारत और समूची मानवता है। वे जब भी कोई योजना लेकर आते हैं तब उस पर तार्किक स्पष्टता भी करते हैं कि यह योजना किस प्रकार सामान्य लोगों के जीवन में और राष्ट्र जीवन में बदलाव करने वाली है। प्रधानमंत्री के रूप में वे लालकिले की प्राचीर से अब तक 12 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। अपने प्रत्येक संबोधन में वे जनकल्याणकारी योजनाओं का पिटारा लेकर आते हैं। सामान्य व्यक्ति को हर बार उत्सुकता रहती है कि इस बार प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या योजना लेकर आ रहे हैं। यही कारण है कि उनके लंबे चलने वाले संबोधनों को भी करोड़ों लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एकाग्रचित होकर सुनते हैं। 15 अगस्त 2025 के संबोधन में लगभग 103 मिनट बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 200 बार देश शब्द का प्रयोग किया, लगभग 100 बार भारत शब्द का और 18 बार राष्ट्र शब्द का। इसी प्रकार उन्होंने लगभग 22 बार आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग किया। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्र के रूप में भारत उनकी आत्मा का विषय है।

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही उन्होंने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया व स्किल इंडिया जैसी विभिन्न योजनाओं को जन आंदोलन का रूप दिया। तदुपरांत वे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़े। वैश्विक महामारी कोरोना ने भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों को अनेक चुनौतियों में डाल दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार स्वदेशी और आत्मनिर्भरता हेतु प्रयास कर रहे थे। 15 अगस्त 2025 के अपने संबोधन में उन्होंने कहा एक राष्ट्र के लिए आत्म सम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। विकसित भारत का आधार भी है- आत्मनिर्भर भारत... आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपया,पैसा, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। सर्वविदित है कि भारत भिन्न-भिन्न रूपों में आत्मनिर्भर ही था लेकिन परतंत्रता के कालखंड ने कुटीर उद्योगों की हत्या कर दी। हम छोटी-छोटी चीजों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर होते चले गए। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी जिस गति और दृष्टि के साथ हमें आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करने चाहिएं थे, वह नहीं हुए। छोटे-छोटे उत्पाद जिन्हें हम तैयार कर सकते थे उनके लिए भी हमारा भरी धन विदेशों में जाता रहा। विगत कुछ समय से वैश्विक फलक पर प्रतिस्पर्धाएं बढ़ रही हैं। संपन्न देश मनमाने टैरिफ और योजनाओं से दूसरे देशों पर दबाव बनाते हैं, ऐसे में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है।

बचत उत्सव का आरंभ तो कुछ वर्ष पहले उनके वोकल फार लोकल के मंत्र से ही हो गया था। उनके आवाह्न से खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई। मिट्टी के दीपक, झालर एवं सजावटी सामान बनाने वाले लोगों की कमाई भी कई गुना हो गई। क्योंकि विदेशी वस्तुएं अपने मूल्य और उपलब्धता में महंगी और पहुंच से बाहर होती हैं। यदि सामान्य व्यक्ति उनके विषय में सोचता है तो उसका बजट बिगड़ना स्वाभाविक है। ध्यातव्य है कि त्योहारी सीजन के आरंभ होने से पहले घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, सूखे मेवे, आइसक्रीम, दवाइयां, कृषि उपकरण, कार व स्कूटर जैसे दैनिक उपयोग वाले सैकड़ों उत्पादों का सस्ता होना सामान्य व्यक्ति के घरेलू बजट के लिए बहुत बड़ी राहत है।

आयकर व जीएसटी सुधारों के बीच उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि- नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही देश में बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है... लोग हर वह सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। देश के गरीब, मध्यम वर्ग, नए मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को इस बचत उत्सव का फायदा होगा। यह भी सर्वविदित है कि आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ऐसे में हमें और आगे बढ़ने के लिए विभिन्न चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। यदि अभी से ही सभी देशवासी स्वदेशी के साथ जुड़कर उत्पादन और उपयोग बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। आज देश में लगातार स्टार्टअप बढ़ते जा रहे हैं। छोटे-छोटे व युवा उद्यमी अपने उत्पाद तैयार कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्धता से इनकी खरीदारी भी आसान हुई है। हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी कटौती से त्योहारी बिक्री 25 प्रतिशत तक बढ़ी है। बाजार में खपत बढ़ने से रोजगार में भी बढ़ोतरी हो रही है। त्योहारी सीजन में खाद्य तेल, वस्त्र- आभूषण, सज्जा के विभिन्न सामान, फ्रिज व टेलीविजन आदि अधिक खरीदे जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बाजारों में ये सामान खूब उपलब्ध हैं। विदेशी उत्पादों की तुलना में ये सस्ते हैं। ऊपर से जीएसटी घटने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की खरीद क्षमता बढ़ी है।

आशा की जा सकती है कि मेड इन इंडिया और कुटीर एवं लघु उद्योग में बने विभिन्न उत्पाद इस बचत उत्सव में लोगों के घरों तक पहुंचेंगे। इससे टैरिफ वार जैसी कारोबारी चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। आवश्यकता इस बात की भी है कि कुटीर एवं लघु उद्योग और स्वदेशी के अनुरूप बने उत्पाद गुणवत्ता और उत्कृष्टता में भी उत्तम हों। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता विकसित भारत की राह में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। नवरात्र से शुरू हुआ बचत उत्सव देश को आर्थिक रूप से विकसित होने में मदद करेगा।

टाटा पावर रिन्यूएबल्स कमीशन ने दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे पर 240 किलोवॉट का पहला हाई-कैपेसिटी मेगाचार्जर लगाया

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली और चंडीगढ़, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL), जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी और प्रमुख ईवी चार्जिंग समाधान प्रदाता है, ने दिल्ली–चंडीगढ़ हाईवे पर अपनी पहली 240 किलोवॉट उच्च क्षमता वाली ईवी मेगा चार्जिंग सुविधा का शुभारंभ किया है। यह उपलब्धि टाटा पावर की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत कंपनी देश के लिए एक भविष्य-तैयार, विश्वसनीय और सुलभ हरित गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है।

इस स्थापना में 240 किलोवॉट क्षमता वाले डिस्पेंसर चार्जर शामिल हैं, जो एक साथ चार वाहनों को चार्ज करने में सक्षम हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों की संगतता भी शामिल है। कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर और चंडीगढ़ के बीच लंबी दूरी की यात्रा को समर्थन देने के लिए उच्च क्षमता वाले ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की है, जिससे इंटरसिटी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सक्षम बनाने में उसकी नेतृत्व भूमिका और सुदृढ़ हुई है।

दिल्ली–चंडीगढ़ हाईवे के व्यस्त मार्ग के मध्य में स्थित (करनाल) यह स्थल रणनीतिक रूप से एक प्रमुख ग्राहक ठहराव बिंदु के रूप में कार्य करता है। ईवी चार्जर को जीवंत सवॉय ग्रीन्स फूड कोर्ट में स्थापित किया गया है, जहाँ कई प्रसिद्ध ब्रांड संचालित हैं। यह स्थान ईवी उपयोगकर्ताओं को ठहरने, ताज़गी पाने और अपने वाहनों को चार्ज करने की उत्कृष्ट सुविधा प्रदान करता है। यह ग्राहक-केंद्रित पहल सततता और जीवनशैली के आदर्श संतुलन को दर्शाती है, जिससे हरित गतिशीलता को और अधिक सुलभ और आकर्षक बनाया जा रहा है।

यह विकास कंपनी के राष्ट्रीय ईवी चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार का हिस्सा है और उसकी स्थिरता पहल "सस्टेनबल इस अटेनबल / अटैनबल" के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को सभी के लिए सुलभ बनाना है। ईवी अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करते हुए, टाटा पावर भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और नेट ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

प्रकृति और विज्ञान का संगम — आधुनिक भारतीय महिला के लिए नया स्किनकेयर वादा

मुख्य संवाददाता

नईदिल्ली। हिमालया वेलनेस ने अपनी ब्यूटी कैटेगरी में अगला कदम बढ़ाते हुए हिमालया टर्मरिक रेंज के लिए नये और आकर्षक अभियान "अनस्पॉट योर नेचुरल ग्लो" की शुरुआत की है। यह पहल 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल टर्मरिक डे के उपलक्ष्य में की गई है।

मशहूर अभिनेत्री और युवा आइकन मिथिला पालकर को दर्शाता यह कैंपेन, हिमालया की 'टर्मरिक रेंज की प्रगति का प्रतीक है।

यह एक ऐसा संग्रह है, लंबे समय से आजमाए जा रहे परंपरागत प्राकृतिक अवयवों को अत्याधुनिक वैज्ञानिक शोध से जोड़ता है, जो त्वचा को देता है प्राकृतिक निखार और प्रामाणिक देखभाल । यह आधुनिक भारतीय महिला के लिए स्किनकेयर की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ता है।

"अनस्पॉट योर नैचुरल ग्लो" संदेश के साथ यह कैंपेन आज की महिलाओं की आकांक्षाओं को दर्शाता है, जो कृत्रिम परिपूर्णता नहीं, बल्कि ऐसा स्वाभाविक निखार चाहती है, जो वास्तविक हो, जो आत्मविश्वास और सेल्फ केयर पर आधारित हो।

हिमालया की टर्मरिक रेंज, जिसमें एक सौम्य फेसवॉश, प्रभावी सीरम और डार्क स्पॉट क्लीयरिंग क्रीम शामिल हैं, को विशेष रूप से स्किनकेयर से जुड़ी उन सामान्य समस्याओं जैसे- डार्क स्पॉट्स और असमान त्वचा टोन को दूर करने के लिए तैयार किया गया है।

लेकिन इससे भी आगे बढ़कर, यह आपकी प्राकृतिक सुंदरता को निखारने का वादा करती है। यह रेंज ऑर्गेनिक टर्मरिक, नायसिनामाइड और ग्लाइकोलिक एसिड के मिश्रण से तैयार की गई है।

राजेश कृष्णमूर्ति, बिज़नेस डायरेक्टर – कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीजन, हिमालया वेलनेस ने कहा, अध्ययनों से पता चलता है कि 80 फीसदी भारतीय महिलाएं असमान त्वचा टोन और डार्क स्पॉट्स की समस्या से परेशान है। यह रेंज हमारी इसी जरूरत का जवाब है - प्रकृति और विज्ञान का ऐसा संगम जो न केवल डार्क स्पॉट्स को साफ करता है बल्कि त्वचा की प्राकृतिक चमक को भी उजागर करता है।"

कैंपेन की विजुअल स्टोरी टेलिंग भी उतनी ही प्रभावशाली है। ब्रांड फ़िल्म को सुनहरी सांझ के प्राकृतिक माहौल और टिमटिमाती जुगनुओं की रोशनी में फिल्माया गया है, यह फ़िल्म उस आत्मविश्वास को खूबसूरती से दर्शाती है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता को अपनाने से आता है।

अपनी बहुमुखी प्रतिभा, करिश्माई व्यक्तित्व और सच्चाई के लिए जानी जाने वाली मिथिला पालकर इस संदेश को जीवंत रूप देती हैं।

मिथिला पालकर ने कहा, "मैं इस विचार से गहराई से जुड़ी हूं कि अपनी प्राकृतिक त्वचा का जश्न मनाया जाए। आज जब दुनिया फिल्टर्स और परफेक्शन की दीवानी है, हिमालया का यह संदेश ताजगी और सशक्तिकरण का अहसास कराता है।"

हिमालया वेलनेस की मार्केटिंग डायरेक्टर – ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, रागिनी हरिहरन ने कहा, "यह अभियान आधुनिक भारतीय महिला को समर्पित है, जो समझदार, आत्मविश्वासी और अपने मूल्यों के अनुरूप स्किनकेयर चाहती है। हल्दी भारतीय स्किनकेयर का सदाबहार हीरो रहा है, और जब इसे नायसिनामाइड और ग्लाइकोलिक एसिड के साथ मिश्रित किया जाता है, तो यह प्रभावी और भरोसेमंद दोनों बन जाता है।"

हिमालया वेलनेस के महाप्रबंधक- फेस केयर कैटेगरी अभिषेक अशत ने कहा, "अनस्पॉट योर नेचुरल ग्लो' कैंपेन के ज़रिए हिमालया टर्मरिक रेंज स्किनकेयर की एक आम समस्या -डार्क स्पॉट्स को सटीक समाधान करता है। आर्गेनिक टर्मरिक को नियासिनमाइड और ग्लाइकोलिक एसिड के साथ मिश्रित करके, हमने एक क्लिनिकली-टेस्टेड फॉर्मूलेशन फार्मूला बनाया है जो डार्क स्पॉट्स को साफ करता है और प्राकृतिक चमक प्रदान करता है, तथा हिमालया के प्रभावी, प्रकृति-समर्थित त्वचा देखभाल के वादे पर खरा उतरता है।"

यह कैंपेन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, रिटेल टचपॉइंट्स और फेस्टिव आउटडोर एक्टिवेशंस के ज़रिए देशभर में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं तक एक मजबूत 360° ब्रांड उपस्थिति बनेगी।

इसके साथ ही, 8 अक्तूबर को इंटरनेशनल टरमरिक डे पर ब्रांड इन्फ्लुएंसर-नेतृत्व वाली एक्टिवेशन भी करेगा, जिसमें देशभर के इन्फ्लुएंसर स्किनकेयर में "गोल्डन रूट" के फ़ायदों पर बात करेंगे।

इस लॉन्च के साथ, हिमालया वेलनेस सिर्फ़ ब्यूटी कैटेगरी में कदम ही नहीं रख रहा, , बल्कि उसे नए मायने भी दे रहा है। टर्मरिक रेंज स्किनकेयर से कहीं बढ़कर है; यह प्रामाणिकता, आत्मविश्वास और प्रकृति-प्रदत्त सुंदरता की ओर एक कदम है।

मिशन आईसीयू और सीपीआर ने 'मिशन क्रिटिकल 2025' का समापन किया, जिससे भारत के लिए राष्ट्रीय महामारी तैयारी रोडमैप का मार्ग प्रशस्त हुआ

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। मिशन आईसीयू, एक स्वयंसेवी-आधारित गैर-लाभकारी संगठन, जो भारत के गहन देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए समर्पित है, ने कम्पैशनेट पेशेंट रिस्पांस, इंक. (सीपीआर) के सहयोग से नई दिल्ली में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन - मिशन क्रिटिकल: 2047 तक महामारी-लचीले भारत की कल्पना - का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन में देश की दीर्घकालिक महामारी तैयारी और स्वास्थ्य प्रणाली के लचीलेपन के लिए एक रोडमैप विकसित करने हेतु सरकार, स्वास्थ्य सेवा, सीएसआर, अनुसंधान आदि क्षेत्रों के नेताओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय थे। श्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, भारत सरकार। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारी की तैयारी राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ हैं जिनके लिए सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के सहयोग की आवश्यकता है। कार्यक्रम की शुरुआत सीपीआर के सह-संस्थापक कृष्णा कोट्टापल्ली के स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद मिशन आईसीयू के सह-संस्थापक डॉ. अश्विन नाइक ने भाषण दिया।

इसके अलावा, कार्यक्रम में एनएचएसआरसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. के. मदन गोपाल और एएमटीजेड के प्रबंध निदेशक एवं संस्थापक सीईओ डॉ. जितेंद्र शर्मा के मुख्य भाषण भी शामिल थे, जिन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन, नवाचार और प्रौद्योगिकी-आधारित स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन पर अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कैसे बहु-क्षेत्रीय साझेदारियाँ देश भर में गहन देखभाल तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अपने दृष्टिकोण को सामूहिक कार्रवाई में बदल सकती हैं।

दिन भर विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चाएँ आयोजित की गईं, जिनमें वित्तपोषकों, चिकित्सकों, मेडटेक नेताओं, स्टार्टअप्स और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के विविध दृष्टिकोण शामिल थे। चर्चाओं में स्थायी स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के निर्माण, किफायती और मापनीय नवाचारों को आगे बढ़ाने, रोग निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने और शहरी-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के बीच की खाई को पाटने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

सम्मेलन के विज़न के बारे में बोलते हुए, डॉ. अश्विन नाइक ने कहा: ₹मिशन क्रिटिकल एक मंच से कहीं अधिक है; यह भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों को भविष्य के लिए तैयार करने का एक सामूहिक प्रयास है। हमारा ध्यान देश के प्रत्येक जिले तक पहुँचने वाले स्थायी, सुलभ क्रिटिकल केयर समाधान बनाने पर है।₹

इस अवसर पर, भारत सरकार के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा, ₹मुझे नीति निर्माताओं, सीएसआर नेताओं और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के दिग्गजों के बीच एक नीति दस्तावेज़ का मसौदा तैयार करने और एक सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण हेतु विचारों को साझा करने में आज के सहयोग को देखकर खुशी हो रही है। यह सामूहिक प्रयास 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इन सिफारिशों को उपयुक्त अधिकारियों को भेजूँगा और ऐसी पहलों का यथासंभव समर्थन करूँगा।"

"मुझे इस मिशन क्रिटिकल कॉन्क्लेव में आकर खुशी हो रही है। यह स्पष्ट रूप से हमारी इस बुनियादी धारणा को चुनौती देता है कि पारंपरिक दृष्टिकोण असाधारण परिणाम दे सकते हैं। मिशन क्रिटिकल उन विचारकों और साझेदारों को एक साथ लाता है जो समकालीन समस्याओं के लिए अनोखे समाधान खोज रहे हैं। इससे न केवल हमारी वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि हमारी भविष्य की स्वास्थ्य प्रणाली को भी और अधिक लचीला बनाने में मदद मिलेगी।₹ कार्यक्रम के दौरान आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन (AMTZ) के प्रबंध निदेशक और संस्थापक सीईओ डॉ. जितेंद्र शर्मा ने कहा।

सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक राष्ट्रीय 2047 महामारी तैयारी रोडमैप की घोषणा थी। यह भारत की स्वास्थ्य सेवा लचीलापन को मजबूत करने के लिए नीतिगत सिफारिशों, विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग और रणनीतियों को दर्शाने वाला एक जीवंत दस्तावेज़ होगा। इस रोडमैप का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2047 तक महामारी की तैयारी के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय ढाँचे की दिशा में सरकारी, निजी और नागरिक समाज के हितधारकों का मार्गदर्शन करना है।

₹मिशन आईसीयू के साथ हमारा सहयोग दर्शाता है कि कैसे दृष्टि और कार्रवाई एक साथ आ सकते हैं। राष्ट्रीय 2047 रोडमैप तैयारियों को संस्थागत बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि स्वास्थ्य सेवा लचीलापन भारत के विकास एजेंडे का एक अभिन्न अंग बन जाए,₹ सीपीआर के सह-संस्थापक डॉ. सत्या गरिमेला ने कहा। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप स्थायी और उच्च-प्रभाव वाली स्वास्थ्य सेवा पहलों के निर्माण में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की आवश्यक भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।

मिशन आईसीयू के सह-संस्थापक मनोज शाह ने रोडमैप के बारे में आगे बात की और कहा कि "महामारी की तैयारियों को इंडिया@100 के विज़न के साथ जोड़कर, हम एक ऐसा ढाँचा तैयार कर रहे हैं जो संकटों को पार कर जाएगा और दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा समानता प्रदान करेगा।"

कार्यक्रम का समापन डॉ. अश्विन नाइक के समापन भाषण के साथ हुआ, जिन्होंने प्रतिभागियों से सम्मेलन से आगे भी सहयोग जारी रखने का आग्रह किया ताकि संवाद को मापनीय कार्रवाई में बदला जा सके जो पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच को बदल दे।

"पोषण भी, पढ़ाई भी" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

रिपोर्ट अंकित गुप्ता कासगंज। गंजडुंडवारा। अनिल राठौर। विकास खण्ड गंजडुंडवारा के मीटिंग हाल में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा "पोषण भी, पढ़ाई भी" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। गंजडुंडवारा में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा "पोषण भी, पढ़ाई भी" अभियान के अंतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को बच्चों के समग्र विकास — विशेष रूप से पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा — से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं।

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक और बौद्धिक विकास पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के साथ-साथ खेल-खेल में पढ़ाई की गतिविधियाँ भी कराई जाएँगी ताकि बच्चे विद्यालय पूर्व अवस्था में ही सीखने की प्रक्रिया से जुड़ सकें। कार्यक्रम में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस अभियान को घर-घर तक पहुँचाने और समुदाय को जागरूक करने का आह्वान किया गया।

हिंदी उर्दू अदबी संगम का 11 को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह

देश-विदेश के ख्याति प्राप्त साहित्यकार करेंगे शिरकत

डॉ.शंभू पंवार

नई दिल्ली । राजधानी की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था हिंदी उर्दू अदबी संगम, दिल्ली आगामी 11 अक्टूबर 2025 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है।

राजधानी के आईटीओ स्थित गालिब इंस्टीट्यूट में होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय भव्य कार्यक्रम के संयोजक डॉ. सैयद अली अख्तर नकवी ने बताया कि विश्व मैत्री और देश की गंगा-जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध समाजसेवी यूएसए से डॉ. इंद्रजीत शर्मा करेंगे एवं मुख्य अतिथि श्रीमती मनीषा शर्मा (राजभाषा प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली),विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ नरेंद्र शर्मा (कुलपति मदरहुड विश्वविद्यालय रुड़की) इंजी. ए.डब्ल्यू.अंसारी (संयुक्त निदेशक एमसीडी दिल्ली), डॉ. सविता चढ़ा (अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार दिल्ली), डॉ. हरिप्रसाद तिमिलिसेना ,(अंतरराष्ट्रीय ख्यातिनाम साहित्यकार नेपाल), प्रवेज अली (पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश), श्रीमती कल्पना पौडेल, (अंतराष्ट्रीय ख्यातिनाम साहित्यकार नेपाल) सुश्री कौशल सुमाली (अंतरराष्ट्रीय ख्यातिनाम साहित्यकार श्रीलंका) उपस्थित रहेंगे।

डॉ. नकवी ने बताया कि समारोह में कवि सम्मेलन, मुशायरा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी होंगी। देश के विभिन्न राज्यों से आए कवि-शायर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, वहीं लोक परंपराओं और संस्कृत कलाकृतियों की झलक भी मंच पर दिखाई जाएगी। इस अवसर पर शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा, विधि, समाज सेवा, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले देश-विदेश के 151 विशिष्ट व्यक्तित्वों को सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष से संस्था ने खेल व अभिभावक सेवा के क्षेत्र में भी विशेष शख्सियतों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह के दौरान प्रतिभागियों केजीवनऔर कार्यों पर आधारित पुस्तक अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनमोल शख्सियत', डॉ. नकवी की कृति 'सफरनामा एक कलमकार', संस्था की परिचय पत्रिका 'मेरे ख्वाब मेरे साथ' और कैलेंडर-2026 का विमोचन भी होगा।

थाना सहसवान क्षेत्र की तकिया की बाजार में पशुओं पर क्रूरता का वीडियो वायरल, शासनादेश होने के बाद भी पशु चिकित्सक नहीं जा रहे बाजारों में, बिना किसी अनुमति के हो रही गौवंश की बिक्री

कानपुर में विस्फोट की जांच में जुटी एटीएस, डीजीपी ने भी हासिल की जानकारी ,चार गंभीर लखनऊ रेफर

सुनील बाजपेई

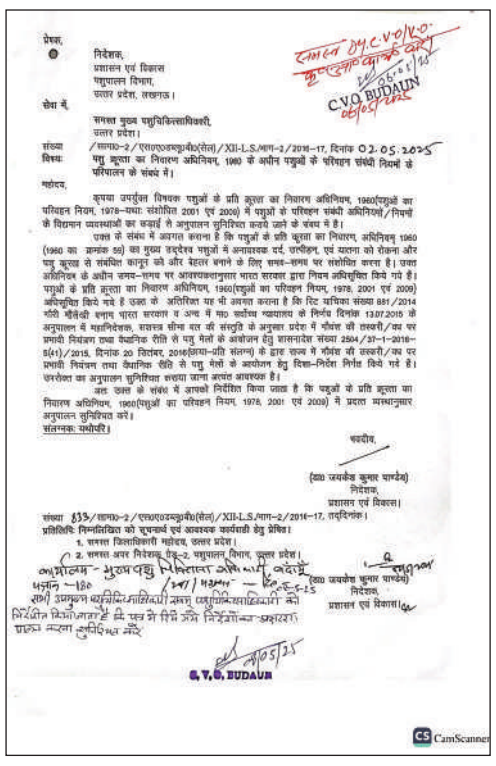

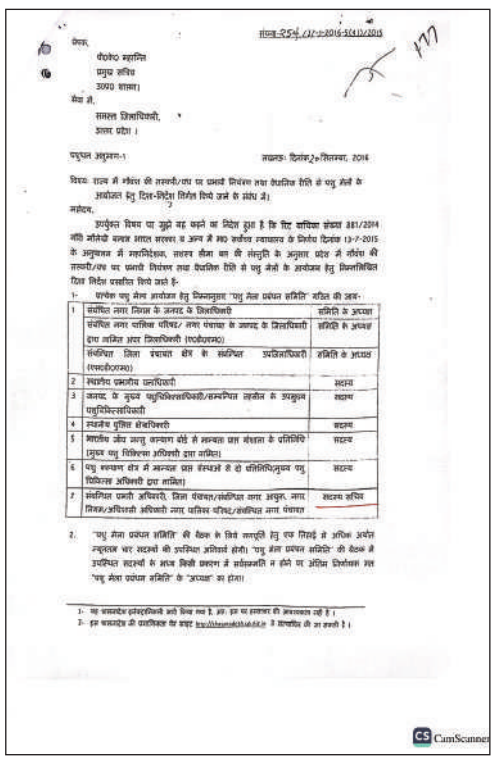

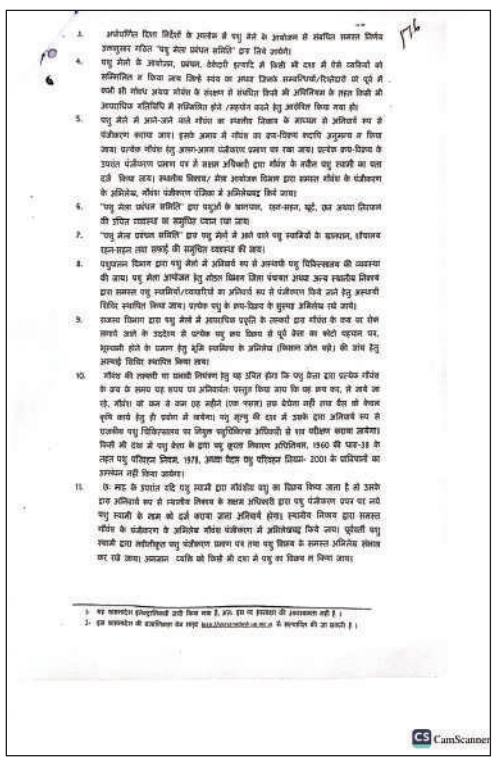

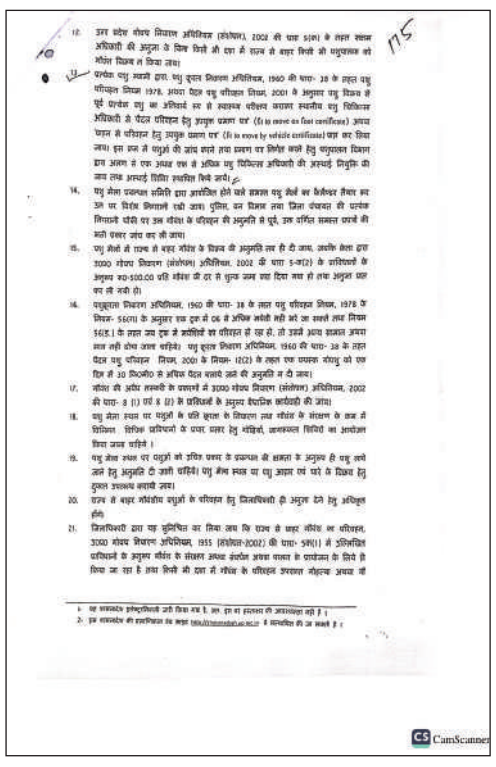

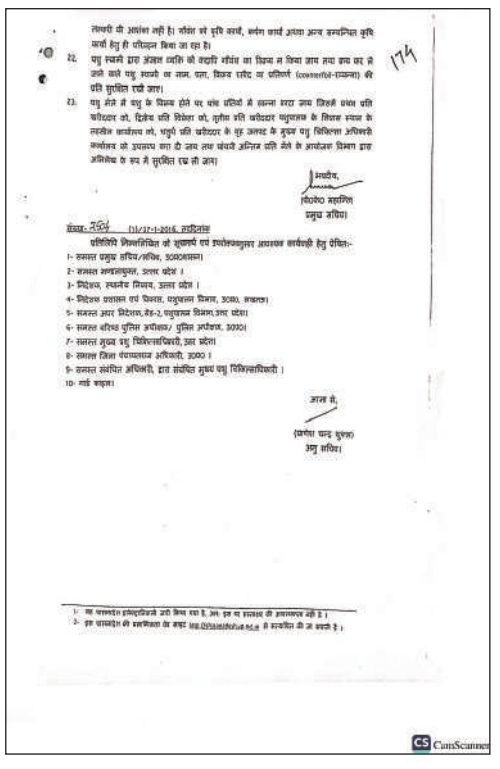

कानपुर। फर्रुखाबाद की तर्ज पर दीपावली के ऐन मौके पर औद्योगिक महानगरी कानपुर में भी हुए भीषण विस्फोट ने हड़कंप मचा दिया है। इस घटना में घायल चार लोगों को इलाज के लिए लखनऊ भी भेजा गया है ,जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई है।वही इस मामले की जांच में एटीएस भी लगातार जुटी हुई है।प्रथम दृष्टया घटना की वजह दोनों स्कूटी में रखे हुए विस्फोटक पटाखे माने जा रहे हैं। वहीं अधिकारियों की घटना में आतंकी साजिश से इनकार कर रहे हैं।

मेस्टन रोड पर मूलगंज के बिसातखाना में हुई इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर अधिकारी जांच में जुट गए हैं। विस्फोट इतना भीषण था की काफी दूर तक आवाज सुनाई दी है। पास की मस्जिद की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। आसपास की कई दुकानों की फाल सीलिंग भी गिर गई है।

वहीं मामले में डीजीपी राजीव कृष्णा ने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल व अन्य अफसरों से घटना की पूरी जानकारी ली। साथ ही कई निर्देश भी दिए। डीजीपी ने फोरेंसिक टीम को मौके से मिले नमूनों की रिपोर्ट जल्दी ही देने को कहा। वहीं एटीएस की दो टीमें लखनऊ से कानपुर पहुंचने के बाद गहन जांच में जुटी हुई है। इन टीमों ने स्थानीय पुलिस की मदद से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए।

इस इस विस्फोट के मामले में पुलिस के अधिकारी हर पहलू पर जांच कर रहे हैं।यह भी माना जा रहा है कि दिवाली के मौके पर पटाखा बनाने के लिए विस्फोटक एक साथ लाया जा रहा हो और उनमें ही धमाका हुआ है।हालांकि धमाके से आसपास की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है, ऐसे में काफी खतरनाक विस्फोटक की आशंका है।

जहां तक घटनाक्रम का सवाल है। यह घटना शाम लगभग सात बजे की है। मूलगंज थाना क्षेत्र के मिश्री बाजार के पास बिसाती बाजार में दो स्कूटियों में धमाका तब हुआ जब बाजार में भीड़ थी और लोग खरीददारी कर रहे थे।घायलों में दुकानदारों के साथ ही कारीगर और ग्राहक भी हैं। कूड़ा बिनने वाली एक किशोरी सुहाना भी घायल हुई है जो बेकनगंज की रहने वाली है। इसके अलावा लाल बंगला निवासी 58 वर्षीय अश्विनी कुमार घायल हुए हैं जिनकी डिप्टी का पड़ाव में दुकान है और वे यहां सामान लेने आए थे।

इसी तरह से अन्य घायलों में ज्वेलरी के कारीगर 35 वर्षीय रईसुद्दीन निवासी पश्चिम बंगाल हाल पता बेकनगंज, बिसात खाना में स्पोर्ट्स उत्पाद के दुकानदार 24 वर्षीय अब्दुल निवासी बिसातखाना, बिसातखाना निवासी बैग के दुकानदार 25 वर्षीय मो. मुर्सलिन और बेल्ट व चश्मे की दुकान में काम करने वाले मीरपुर निवासी 15 वर्षीय जुबीन शामिल हैं।

जेपीसी कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार के अनुसार प्राथमिक जांच में धमाका पटाखे में होने की बात सामने आ रही है।

समाचार लिखे जाने तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस ने स्कूटी मालिक को तलाश लिया है। वह कानपुर का ही एक युवक है, जो पिता के साथ खरीदारी करने बाजार आया था। उसने पटाखे खरीद कर स्कूटी में रखने की बात कही है। संभवतः दबाव पड़ने से पटाखों में विस्फोट हुआ है। स्कूटी मालिक के पिता भी घायल हुए हैं, उनका इलाज हो रहा है। घायलों व मौके पर मौजूद रहे अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक की जांच के मुताबिक यह आतंकी घटना या साजिश नहीं है। पुलिस के मुताबिक गहन जांच लगाता जारी है, जिससे घटना वजह जल्द ही पता चल जाएगी इसके बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।

गंजडुंडवारा में मिशन शक्ति फेस-5 कार्यक्रम का हुआ आयोजन:सीओ रहे मौजूद, छात्राओं को विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी

रिपोर्ट अंकित गुप्ता कासगंज। कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा नगर में स्थित पीजी कॉलेज में गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति फेस-5 अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पटियाली के क्षेत्राधिकारी संदीप वर्मा ने की, जिसमें गंजडुंडवारा कोतवाली प्रभारी भोजराज अवस्थी भी मौजूद रहे।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी संदीप वर्मा ने छात्राओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं और साइबर धोखाधड़ी से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया। मिशन शक्ति टीम ने कॉलेज की छात्राओं को सरकारी योजनाओं, सुरक्षा उपायों और आत्मनिर्भरता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।

अपने संबोधन में क्षेत्राधिकारी संदीप वर्मा ने बताया कि मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

उन्होंने स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं से कहा कि यदि रास्ते में कोई छेड़खानी करता है, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1090 या 112 पर कॉल करें। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचेगी। उन्होंने छात्राओं को निर्भीक होकर स्कूल, कॉलेज या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जाने का आश्वासन दिया ।कार्यक्रम में कॉलेज का समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहा।

बालिकाओं में आज की सशक्त लड़की के साथ कल की कार्यकर्ता, उद्यमी, घर का मुखिया, संरक्षक ,राजनीतिक नेता दोनों होने की क्षमता है

दुनियाँ को बदलने के लिए सही साधनों के साथ बालिकाओं को सुरक्षित शिक्षित सशक्त और स्वस्थ जीवन शैली सुनिश्चित करना समय की मांग – **एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र**

भारत में आदिअनादि काल से भारतीय संस्कृति में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता रहा है। उन्हें देवियों का अवतार माना जाता रहा है, परंतु बड़े बुजुर्गों की कहावत सत्य ही है कि, समय कभी एक सा नहीं रहता परंतु उनकी वह भी शिक्षा है कि वह अपनी सकारात्मक सोच सच्चाई नारी सम्मान परमार्थ बुरी नजर से बचना सहित अनेक गुणों को समय के साथ न बदलते हुए स्थाई रखना मानवीय स्वभाव में समाहित करना जरूरी है। परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया इनकी स्थिति में काफी बदलाव आया, लड़कियों के प्रति लोगों की सोच बदलने लगी, बालविवाह प्रथा, सती प्रथा, दहेज़ प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि रुढ़िवादी प्रथायें काफी प्रचलित हुआ करती थी, इसी कारण लड़कियों को शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार और चिकित्सा जैसे अधिकारों से वंचित रखा जाने लगा था, मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि अब इस आधुनिक युग में लड़कियों को उनके अधिकार देने और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है और कई योजनायें लागू कर रही है। इसलिए आज हम मीडिया के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से दुनिया को बदलने के लिए सही साधनों के साथ बालिकाओं को सुरक्षित शिक्षित सशक्त और स्वस्थ जीवन शैली सुनिश्चित करना समय की मांग है इसपर चर्चा करेंगे

साथियों बात अगर हम बालिकाओं की शक्ति को साकार करने में निवेश की करें तो, ये एक असाधारण रूप से महत्वपूर्ण चरण से गुजरती हैं जहां उन्हें एक सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ जीवन शैली सुनिश्चित करके दुनिया को बदलने के लिए सही साधनों के साथ सशक्त बनाया जा सकता है। उनमें आज की सशक्त लड़की के साथ-साथ कल की कार्यकर्ता, मां, उद्यमी, संरक्षक, घर का मुखिया या राजनीतिक नेता दोनों होने की क्षमता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, किशोरियों की शक्ति को साकार करने में निवेश आज उनके अधिकारों को कायम रखता है और एक अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य का वादा करता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक संघर्ष की समस्याओं को हल करने में आधी मानवता एक समान भागीदार है, आर्थिक विकास, बीमारी की रोकथाम और वैश्विक स्थिरता।

साथियों बात अगर हम भारत की करें तो, भारतीय समाज में सदियों से बेटियों को कई प्राचीन कुप्रथाओ, रीति-रिवाजों, के चलते प्रताड़ति होना पड़ा है। आज भी निर्भया जैसा कांड शर्मनाक है। कहने को हम आधुनिक हो चले हैं पर आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें सुनकर समाज का असभ्य चेहरा सामने आता है। आज भी भारतीय समाज में भ्रूण हत्या, दहेज़ प्रथा, यौन शोषण, बलात्कार जैसे अनैतिक कृत्य नहीं रुक रहे हैं। प्रशासन के साथ-साथ हर निजी व्यक्ति की भी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। बेटियों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्यों का महत्तव, महान महिलाओं की गाथाओं और धार्मिक संस्कारों से परिचित कराना अभिभावकों का कर्तव्य है ।बाहर ही नहीं बल्कि घर में भी वह भेदभाव, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना हमारा पहला दायित्व है और नैतिक अनिवार्यता भी। शिक्षा से लड़कियां न सिर्फ शिक्षित होती हैं बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा होता है। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं साथ ही यह गरीबी दूर करने में भी सहायक होती है।

साथियों हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार ने 2015 में योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य देश में हर बालिका को शिक्षा प्रदान करना है। यह बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को भी संबोधित करता है। योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सुरक्षा करना है। यह योजना त्रि-मंत्रालयी प्रयास है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और 2015 में विश्व नेताओं द्वारा अपनाए गए इसके 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में प्रगति के लिए एक रोडमैप शामिल है जो टिकाऊ है और किसी को पीछे नहीं छोड़ता है। 17 लक्ष्यों में से प्रत्येक लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने का अभिन्न अंग है।

साथियों बात अगर हम बदलते परिपेक्ष की करें तो, वक़्त के साथ समाज की प्राथमिकताएं बदलती है सोच और आदतें बदलती है निरंतर विकास की ओर कदमों की छाप बढ़ती जाती है इसी तरह ग्रामीण लोगों के नज़रिये में बदलाव आने लगा है। अब वह न केवल लड़कियों को क्रिकेट - फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित करने लगे हैं बल्कि इससे जुड़ी हर गतिविधियों में सहयोग भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है लैंगिकता के मायने लड़कियों और लड़कों, महिलाओं और पुरुषों में महिलाओं ने समानता सदैव चुनौतियों का सामना किया चाहे ग्रामीण इलाकों रहे हो या शहरी। ग्रामीण क्षेत्र अब भी

> साथियों बात अगर हम भारत की करें तो,भारतीय समाज में सदियों से बेटियों को कई प्राचीन कुप्रथाओ, रीति-रिवाजों, के चलते प्रताड़ति होना पड़ा है। आज भी निर्भया जैसा कांड शर्मनाक है। कहने को हम आधुनिक हो चले हैं पर आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें सुनकर समाज का असभ्य चेहरा सामने आता है। आज भी भारतीय समाज में भ्रूण हत्या, दहेज़ प्रथा, यौन शोषण, बलात्कार जैसे अनैतिक कृत्य नहीं रुक रहे हैं। प्रशासन के साथ-साथ हर निजी व्यक्ति की भी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है।

महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चाहे पहनावे से लेकर हो या नौकरी करने तक इक़ संकुचित सोच के दायरे में सिमटा हुआ है।

साथियों बात अगर हम महिलाओं के हक में कानून व्यवस्थाएं बनाने की करें तो इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण क़ा करना है, क्योंकि लिंगआधारित चुनौतियों को समाप्त करता है, जिसका सामना दुनिया भर में लड़कियां करती हैं, जिसमें बाल विवाह, उनके प्रति भेदभाव और हिंसा शामिल है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

खिलती हुई कलियाँ हैं बेटियाँ,
माँ-बाप का दर्द समझती हैं बेटियाँ,
घर को रोशन करती हैं बेटियाँ,
लड़के आज हैं तो आने वाला कल हैं बेटियाँ।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि दुनिया को बदलने के लिए सही साधनों के साथ बालिकाओं में आज की सशक्त लड़की के साथ कलकी कार्यकर्ता मां उद्यमी संरक्षक घर का मुखिया राजनीतिक नेता दोनों होने की क्षमता है इसलिए उन्हें सुरक्षित शिक्षित सशक्त और स्वस्थ जीवन शैली सुनिश्चित करना समय की मांग है।

संघ के सौ बरस का इकलौता हासिल

(आलेख : राजेंद्र शर्मा)

दो दिनों में फैले आरएसएस के शताब्दी वर्ष के केंद्रीय आयोजनों ने जितने बलपूर्वक उसके बुनियादी तौर पर एक राजनीतिक संगठन और वर्तमान सत्ता की राजनीति करने वाला संगठन होने की सचाई को उजागर किया है, उतने बलपूर्वक दूसरे किसी घटनाक्रम ने नहीं किया होगा। पहले दिन, 1 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस के वफादार स्वयंसेवक और धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री के बीच का अंतर पूरी तरह से मिटाते हुए, आरएसएस के सौ वर्ष पूरे होने के मौकेे पर विशेष डाक टिकट तथा सौ रुपये का विशेष सिक्का जारी करने के जरिए और इस मौके पर अपने विस्तृत संबोधन से यह काम किया। और दूसरे दिन, 2 अक्टूबर को आरएसएस के सरसंघचालक, मोहन भागवत ने अपने सालाना दशहरा संबोधन में, इस समय की अपनी सबसे बड़ी चिंता को स्वर देते हुए, वही काम किया। कहने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस के प्रचार की असली धुरी, उसका यह बड़ा झूठ रहा है कि वह तो राजनीति से निरपेक्ष रहकर, राष्ट्र की सेवा करने वाला संगठन है !

पहले दिन, प्रधानमंत्री ने आरएसएस के लिए एक विस्तृत प्रशस्ति पत्र पढ़ने के साथ, उसके 100 वर्ष होने के उत्सव के रूप में 100 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया। बेशक, यह पहली बार नहीं था जबकि इस तरह विशेष सिक्का जारी किया जा रहा था। दुर्लभ ही सही, ऐसे मौके पहले भी आए हैं, जिनके सेलिब्रेशन के तौर पर विशेष सिक्के जारी किए गए हैं। फिर भी, इस सिक्के के जारी किए जाने में कुछ ऐसा था, जो पहली बार किया जा रहा था। और यह कितने सुचिंतित तरीके से किया जा रहा था, इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, इसके पहले स्वतंत्र भारत में पहली ही बार किये जाने को अलग से रेखांकित करना जरूरी समझा। और जो पहली बार किया जा रहा था, वह था सरकार द्वारा जारी इस सिक्के पर, जहां एक तरफ राष्ट्र चिन्ह, अशोक स्तंभ उकेरा गया है, वहीं दूसरी ओर, एक समानांतर राष्ट्र चिन्ह के रूप में, तथाकथित "भारत माता" का चित्र उकेरा गया है।

पुनः यह कथित भारत माता, हाथ में भारत के राष्ट्रध्वज के बजाए, आम तौर पर हिंदू धार्मिक परंपराओं और मंदिरों से जुड़ा हुआ, बीच में कटाववाला मुखर रूप से हिंदू-ध्वज लिए हुए है। और चित्र में आरएसएस की पहचान कराने वाली वेशभूषा में तीन स्वयंसेवक, इस हिंदू ध्वजाधारी भारत माता को आरएसएस का खास हस्त प्रणाम कर रहे हैं, जो वास्तव में विदेशी नाजी परंपराओं से आया है। यह पूरा का पूरा चित्र, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जिस आरएसएस के 100 साल होने का उत्सव, एक सरकारी आयोजन के जरिए भारत के प्रधानमंत्री मना रहे थे, वास्तविक भारतीय राष्ट्रीय चिन्हों को नकार कर, उनकी जगह वैकल्पिक बहुसंख्यक-धार्मिक परंपरा के और वास्तव में बहिष्करणवादी चिन्हों को, राष्ट्रीय चिन्हों के रूप में स्थापित करने का एक सचेत प्रोजैक्ट है। यह दूसरी बात है कि इस सचाई को पेश करते हुए भी, इस पर राष्ट्रवाद का पर्दा डालने की कोशिश भी की जाती है और संस्कृत में कथित रूप से आरएसएस का आप्त वाक्य भी इस चित्र के साथ डाल दिया जाता है — सब राष्ट्र का, मेरा कुछ नहीं।

यहां यह याद दिलाना अप्रासांगिक नहीं होगा कि भारत माता की आरएसएस की उक्त संकल्पना, जिसे अब एक ही झटके में स्वयंसेवक प्रधानमंत्री द्वारा देश की सरकारी मुद्रा पर बैठा दिया गया है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐतिहासिक रूप से उभर कर आयी, भारत माता की ही संकल्पना से न सिर्फ सचेत रूप से भिन्न है, बल्कि उसके समानांतर गढ़ी गयी है। यह एक जाना-माना तथ्य है कि भारत माता की संकल्पना पहले-पहल, अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक चित्र रूप में पेश की थी। लेकिन, अवनींद्र नाथ की कल्पना की भारत माता वास्तव में 'भारत माता ग्राम वासिनी' थी — अपने रूप, भाव और सज्जा में, देवियों की तमाम हिंदू संकल्पनाओं से बहुत भिन्न। इस भारत माता का वेष एक साध्वी का है, जिसके पीछे बंकिम चंद्र चैटर्जी की रचना, आनंद मठ की प्रेरणा मानी जाती है। चार हाथ वाली इस भारत माता के एक हाथ में, भारत की कृषि प्रधानता को रेखांकित करते हुए, धान का एक छोटा सा गट्ठर भी दिया गया था। शेष तीन हाथों में एक में अगर रुद्राक्ष माला है, तो एक हाथ में पोथी है और तीसरे हाथ में कपड़े का टुकड़ा है। वास्तव में यह भारत माता भी मूल रूप में 'बंग माता' थी, जिसे जन स्वीकृति ने 'भारत माता' के आसन तक पहुंचाया था। इसके बरक्स आरएसएस लंबे अर्से से, एक शेर की सवारी करने वाली देवी की, लोक जीवन से बहुत दूर की कल्पना को, 'भारत माता' की संकल्पना के रूप में स्थापित करने में लगा हुआ था।

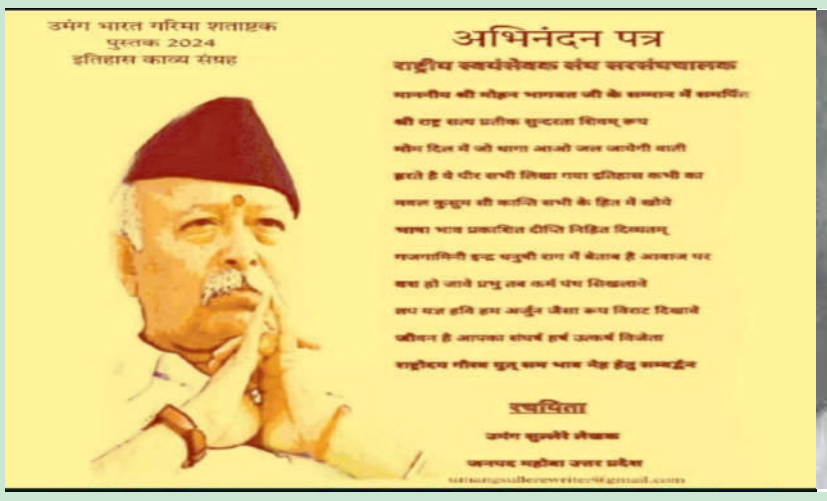

और अब स्वयंसेवक के प्रधानमंत्री होने के बल पर, कम से कम समारोही सरकारी सिक्के में तो, इसे स्थापित करने में कामयाब भी हो गया है। और उसी वृहत्तर प्रोजैक्ट के हिस्से के तौर पर, राजसत्ता तक पहुंच हासिल होने के 100 साल के इसी हासिल के बल पर, इसी मौके पर जारी किए गए डाक टिकट के जरिए, स्वतंत्र भारत की जानी-मानी वास्तविकता से अलग, एक समानांतर इतिहास रचने का प्रयास भी किया गया है। डाक टिकट पर प्रकाशित चित्र में 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में, अपनी पहचान कराने वाली पोशाक में ही, आरएसएस के स्वयंसेवकों को परेड करते दिखाया गया है। यह चुनाव भी कितने सचेत रूप से किया गया, इसका अंदाजा भी इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, इस चित्र की कथा की ओर विशेष रूप से ध्यान खींचा है, ताकि इस चित्र को आधिकारिक राष्ट्रीय जीवन में आरएसएस की स्वीकार्यता का अकाट्य साक्ष्य बनाया जा सके।

यह इसके बावजूद है कि इसी सिलसिले में आरएसएस द्वारा समय-समय पर किए जाते रहे दावों को चुनौती देते हुए, ये तथ्य प्रमाणों के साथ सामने आ चुके हैं कि भारत-चीन सीमा झड़प के समय आरएसएस की किसी भूमिका को देखते हुए, जवाहरहाल नेहरू द्वारा आरएसएस को 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किये जाने का दावा, कोरी गप्प है। इसके बरक्स, सचाई यह है कि 1963 की गणतंत्र दिवस परेड, एक सैनिक परेड के बजाए मूलतः एक जन परेड के रूप में आयोजित की गयी थी, जिसमें आम जनता को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया था और एक लाख से ज्यादा लोग शामिल भी हुए थे। अलबत्ता इस मौके का बेनिफिट लेते हुए, आरएसएस ने संगठित तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को अपनी खास पोशाक में इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा था, जबकि सरकार ने भी जनता को आम नियंत्रण देने के बाद, किसी को भी रोकने की जरूरत नहीं समझी। जाहिर कि संघ की राष्ट्रीय स्वीकार्यता का यह झूठ भी, अब केंद्र में सत्ता पर नियंत्रण के जरिए, सरकारी डाक टिकट के जरिए, देश से मनवाने की कोशिश की जा रही है।

इस मौके पर प्रधानमंत्री के संबोधन में आरएसएस का विरुद गायन करने के लिए, जिस तरह लगातार और बार-बार शुद्ध झूठ का सहारा लिया गया है, उसके ब्यौरे में जाना इस टिप्पणी में हमारे लिए संभव नहीं है। यहां इतना कहना ही काफी होगा कि उनके संघ के संबंध में झूठे दावों की सूची बनाने बैठें, तो पूरा लेख उसी में खत्म हो जाएगा। यहां हम सिर्फ इतना ध्यान दिलाना चाहेंगे कि 15 अगस्त के लाल किले के अपने संबोधन ने प्रधानमंत्री ने, आरएसएस का सरासर झूठा महिमा मंडन करने के लिए, इतिहास को साफ तौर पर तोड़ने-मरोड़ने की जो शुरूआत की थी, उसे अब उन्होंने उत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। यह तोड़-मरोड़ 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस की मौजूदगी की दुर्व्याख्या तक ही सीमित नहीं रहती है। उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की 'भूमिका' के झूठे अतिरंजित दावों से लेकर, आरएसएस के 'सामाजिक समरसता' के पाखंड को उधार की विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए, गांधी से लेकर डा. आंबेडकर तक के मुंह से आरएसएस की प्रशंसा कराने तक के झूठ शामिल हैं। और इसमें स्वतंत्र भारत में पचहत्तर साल में आरएसएस की भूमिका को लेकर झूठ भी, जिसमें महात्मा गांधी की हत्या से लेकर, बाबरी मस्जिद के ध्वंस तक, अक्षम्य करतूतों के सिलसिले में आरएसएस पर स्वतंत्र भारत में लगायी गयी पाबंदियों को उस पर 'राजनीतिक अत्याचार' बताने का महाझूठ भी। और यह सिलसिला, आरएसएस के नंबर बढ़ाने के लिए, इतने हाल के इतिहास को नंगई से झुठलाने की हद तक जाता है कि 'आज भी पंजाब में बाढ़, हिमाचल तथा उत्तराखंड में तबाही तथा केरल में वायनाड में त्रासदी जैसी आपदाओं में स्वयंसेवक सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वालों में थे।' लेकिन, मीडिया की खबरों के मुताबिक भी सचाई यह है कि एकदम हाल की इन आपदाओं में से किसी में भी, आरएसएस कहीं दिखाई तक नहीं दिया है। झूठे प्रचार के बल पर, झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में संघ और उसके स्वयंसेवकों के हिटलरी भरोसे का कोई ओर-छोर ही नहीं है।

और दूसरे दिन, आरएसएस सरसंघचालक भागवत, न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर समेत, हर क्षेत्र में मोदी सरकार को कामयाबी के सार्टिफिकेट देकर और युवाओं तक के मामले में उसकी कारगुजारियों पर संतोष जताकर, मोदी शासन से अपनी अभिन्नता का तथा अपनी राजनीतिक वचनबद्धता का प्रमाण देते हैं, वह श्रीलंका, बांग्लादेश तथा नेपाल के हाल के घटनाविकास से वह बहुत ही चिंतित भी नजर आते हैं। "श्रीलंका में, बांग्लादेश में और हाल ही में नेपाल में जिस प्रकार जन-आक्रोश का हिंसक उद्रेक होकर सत्ता का परिवर्तन हुआ है, वह हमारे लिए चिंताजनक है।" अपने स्तर पर भागवत इशारों में वर्तमान शासन को आगाह भी करते नजर आते हैं कि, "शासन प्रशासन का समाज से टूटा हुआ संबंध, चुस्त तथा लोकाभिमुख प्रशासकीय क्रिया कलापों का अभाव, यह असंतोष के स्वाभाविक तथा तत्कालिक कारण होते हैं।" फिर भी षडयंत्र का डर दिखाने का आसान रास्ता लेते हैं: "अपने देश में तथा दुनिया में भी, भारतवर्ष में इस तरह के उपद्रवों को चाहने वाली शक्तियां सक्रिय हैं।" और इसके बाद फौरन, इस तरह के संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी वैचारिक तलवार लेकर कूद पड़ते हैं:"हिंसक उद्रेक में वांछित परिवर्तन लाने की शक्ति नहीं होती। प्रजातांत्रिक मार्गों से ही समाज ऐसे अमूलाग्र परिवर्तन ला सकता है।" साफ है कि आरएसएस, जिसकी हमेशा से राजसत्ता पर ही नजर लगी हुई थी, सौ साल के हासिल के रूप में राजसत्ता तक अपनी पहुंच से जहां गदगद् है, वहीं इस हासिल के हाथ से फिसल जाने के खतरे से डरा भी हुआ है। झूठ पर खड़े उसके साम्राज्य के पांव जो नहीं हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक पत्रिका 'लोकलहर' के संपादक हैं।)

क्या भारत की कोचिंग संस्कृति को समाप्त करने के लिए आसान जेईई मेन, नीट यूजी परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं?

विजय गर्ग

जैसा कि भारत जेईई और नीट में आसानी लाने पर बहस कर रहा है, वास्तविक चुनौती प्रश्न पत्रों से परे है। वास्तविक न्याय इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रणाली असमानता, परीक्षा तनाव और कोचिंग संस्कृति से कैसे निपटती है जो लाखों भविष्यों को आकार देती है। जैसे-जैसे सरकार भारत की दो सबसे प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं, जेईई और नीट में कठिनाई के स्तर को संशोधित करने पर विचार कर रही है, एक महत्वपूर्ण बहस फिर से सामने आई है: क्या परीक्षा कठोरता वास्तव में प्रणाली को अधिक निष्पक्ष बना सकती है? हर साल लाखों छात्र इन उच्च जोखिम वाले परीक्षणों पर अपना भविष्य दांव लगाते हैं, जो न केवल कॉलेज प्रवेश निर्धारित करते हैं बल्कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को छाया देने वाली बहुअरब रुपये की कोचिंग उद्योग को भी आकार देते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में न्याय, समावेशिता और छात्रों की भलाई के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए जेईई मेन और नीट-यूजी की कठिनाइयों की समीक्षा करने की योजना की घोषणा की। लेकिन जैसे-जैसे चर्चाएं तेज होती जा रही हैं, शिक्षकों, छात्रों और नीति निर्माताओं में इस बात पर मतभेद हो रहे हैं कि क्या इन परीक्षाओं को आसान बनाना समानता को बढ़ावा देगा या दबाव को कहीं और ले जाएगा। कोचिंग कल्चर CONUNDRUM वर्षों से जेईई और नीट की कठिनाई ने भारत के उभरते कोचिंग पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है। कोटा से हैदराबाद तक, छात्र कई वर्षों और अपने माता-पिता की बचत में व्यस्त रहते हैं जो अक्सर रूट लर्निंग और टेस्ट लेने के लिए उत्सुकता और समझ को प्राथमिकता देते हैं। यदि परीक्षा कठिनाई कम हो जाती है तो हम कोचिंग उद्योग में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने की उम्मीद कर सकते हैं - आसान परीक्षाएं कोचिंग केंद्रों को फॉर्मूला ड्रिल सत्रों से छात्रों की अवधारणात्मक स्पष्टता और करियर कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। ₹यह उद्योग को एक संकीर्ण परीक्षा-केंद्रित प्रक्रिया से शैक्षणिक और व्यक्तिगत सफलता दोनों पर केंद्रित विविध शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में बदल सकता है, जब स्कूलों और परीक्षाओं के बीच सबसे बड़ी चुनौतियां स्कूली पाठ्यक्रमों और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के संबंध में नहीं हैं। स्कूलों में समग्र विकास और अवधारणागत आधार पर जोर दिया जाता है, जबकि जेईई और एनआईईटी तेजी, सटीकता और आवेदन-आधारित समस्या समाधान की मांग करते हैं। विद्यालय का पाठ्यक्रम और प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं विभिन्न लक्ष्यों के साथ डिज़ाइन की जाती हैं।₹ दोनों को संरेखित करना परीक्षा कठिनाई कम करने से अधिक प्रभावी हो सकता है। इससे कोचिंग पर निर्भरता कम हो जाएगी, लगातार तैयारी सुनिश्चित होगी और परीक्षाएं चुनौतीपूर्ण लेकिन निष्पक्ष रहेंगी ₹कोचिंग गति और रणनीति के साथ मदद करता है, लेकिन स्कूल नींव बनाते हैं।

दोनों एक-दूसरे की पूर्ति करते हैं, स्कूल ज्ञान को बढ़ावा देते हैं और प्रशिक्षण इसे तेज करता है। ₹फायरनेस बनाम योग्यता: नीति निर्माताओं के लिए केंद्रीय चुनौती समानता और उत्कृष्टता के बीच संतुलन ढूंढना है।₹ एक वरिष्ठ शिक्षक कहते हैं, ₹केवल कठिनाई को कम करना समावेशीता सुनिश्चित नहीं कर सकता।₹ उन्होंने बताया, ₹यह दबाव को कहीं और ले जा सकता है।₹ वास्तविक योग्यता तर्क और समझ का प्रतिबिंब होनी चाहिए, महंगी कोचिंग या नियमित यादों तक पहुंच नहीं।₹ - निष्पक्षता का अर्थ है कि प्रत्येक छात्र को क्षमता प्रदर्शित करने के लिए समान अवसर होना चाहिए। सुधारों को अनुकूलनात्मक मूल्यांकन, परियोजना-आधारित सीखने और वंचित छात्रों के लिए ऑनलाइन सहायता प्रणालियों जैसे कई उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विजय गार्ग का तर्क है कि निष्पक्ष संसाधन, डिजिटल मार्गदर्शन और मॉड्यूलर परीक्षाएं प्रदान करने वाले पायलट कार्यक्रम भारत को ₹मल्टी-पाथ मूल्यांकन मॉडल₹ की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, जो दबाव के तहत गति परीक्षण करने के बजाय विविध प्रतिभाओं को महत्व देता है। उन्होंने कहा, ₹टेक ने शैक्षिक समानता के लिए नेतृत्व किया। सरकार का ध्यान डेटा-सूचित, प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों के माध्यम से इक्विटी बनाने पर केंद्रित होना चाहिए।₹ ₹हम छात्रों का मूल्यांकन और तैयारी के तरीके में सुधार किए बिना परीक्षाओं को आसान बनाना, केवल मौजूदा असमानताओं को मजबूत करेगा।₹ जीएसआरजी एआई-समर्थित और साक्ष्य आधारित आकलन प्लेटफार्मों की वकालत करता है जो परीक्षण डिजाइन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। उनके आंतरिक विश्लेषण से पता चलता है कि जब स्कूल राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के अनुरूप माइक्रो-मूल्यांकन अपनाते हैं, तो ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच प्रदर्शन अंतर 10-15 प्रतिशत कम हो जाता है जिससे यह साबित होता है कि निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणालीगत विभाजन को संकुचित कर सकता है। गार्ग कहते हैं कि आगे का रास्ता स्कूलों में नैदानिक और शैक्षिक मूल्यांकन को शामिल करना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षाएं ₹ट्रिक₹ प्रश्नों के बिना एनसीईआरटी विनिर्देशों के अनुरूप रहें। उन्होंने जोर देते हुए कहा, ₹समानता को कम करके नहीं बनाया जाता है, लेकिन प्रत्येक छात्र को प्रौद्योगिकी, शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम पुनः डिजाइन के माध्यम से मजबूत आधार बनाने की अनुमति देकर₹ शैक्षणिक बहस के नीचे एक गहरी चिंता होती है: इन परीक्षाओं का मनोवैज्ञानिक नुकसान। कोचिंग हबों में आत्महत्याओं की खबर से लेकर आवेदकों के बीच पुरानी चिंता तक, भारत का परीक्षा दबाव संकट निर्विवाद है - जेईई और नीट जैसी उच्च-स्तरीय परीक्षाएं छात्रों के लिए तनावपूर्ण और चिंता पैदा करने वाली सभी चीजों को दर्शाती हैं

मानसिक स्वास्थ्य समीकरण

शैक्षणिक बहस के नीचे एक गहरी चिंता है: इन परीक्षाओं का मनोवैज्ञानिक नुकसान। कोचिंग हब में आत्महत्याओं की खबरों से लेकर आवेदकों के बीच पुरानी चिंता तक, भारत का परीक्षा दबाव संकट निर्विवाद है।

जेईई और नीट जैसी उच्च-स्तरीय परीक्षाएं छात्रों के लिए तनावपूर्ण और चिंताजनक हैं

यद्यपि गार्ग यह स्वीकार करते हैं कि आसान परीक्षाएं तनाव को अस्थायी रूप से कम कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि इसका समाधान कहीं और स्थित है: ₹यदि परीक्षाओं को सरल किया जाए तो भी प्रतिस्पर्धा नए रूपों में फिर से दिखाई देगी। वास्तविक सुधार का अर्थ है मानसिक कल्याण, कौशल-आधारित मूल्यांकन और प्रणाली में मार्गदर्शन

विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि परीक्षा में कठिनाई को समायोजित करना पर्याप्त नहीं हो सकता है। वास्तविक सुधार में संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, पाठ्यक्रमों को संरेखित करना, तैयारी संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, मानसिक कल्याण को एकीकृत करना और जिज्ञासा को प्रतिस्पर्धा के रूप में महत्व देना। ₹इक्विटी-समर्थक नीतियों को छात्रों के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए कई मार्ग बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल मानकों को कम करना

सरकार की प्रस्तावित समीक्षा एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करती है: 21वीं सदी के भारत में शिक्षा में न्याय का क्या अर्थ होता है। आसान परीक्षाएं कोचिंग संस्कृति को ठीक कर सकती हैं या नहीं, असली परीक्षण यह है कि प्रणाली योग्यता को कैसे परिभाषित करती है और वह किसको पीछे छोड़ती है।

सेवानिवृत्त प्रधान शैक्षिक स्तंभकार

पीओके : गंभीर रणनीतिक भूल होगा भारत में विलय का संकल्प

हरीश शिवनानी

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ने के साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को भारत में शामिल करने की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ रही है। कुछ उच्च-स्तरीय बयानों ने इस मुद्दे को नए सिरे से जीवंत कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही एक सार्वजनिक सभा में स्पष्ट कहा कि ₹पीओके हमारा है और बिना किसी आक्रामक कार्रवाई के यह भारत का हिस्सा बनेगा।₹ इसी क्रम में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी बीकानेर में पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में दिखाया गया संयम अब दोहराया नहीं जाएगा। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या वह नक्शे में बने रहना चाहता है या नहीं। ये बयान भारतीय जनमानस को भी उद्वेलित कर रहे हैं। भारत का जनमानस आज भी 1948 में की गई उस ऐतिहासिक महाभूल को भुला नहीं पाया है जब पाकिस्तान के कश्मीर पर थोपे गए युद्ध में भारतीय सेना उसे खदेड़ रही थी पर नेहरु सरकार ने सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और भारतीय कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया, वही पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहलाता है। 1948 से भारतीयों का स्वप्न है कि पीओके को वापस भारत में मिलाया जाए। यह एक भावुक स्वप्न है लेकिन गहन विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि आज के दौर में पीओके को सैन्य या कूटनीतिक रूप से वापस लेना भारत के लिए एक गंभीर रणनीतिक भूल साबित होगी।

पीओके की जटिल और ख़स्ता आर्थिक परिस्थितियां, जनसांख्यिकीय, भू-राजनीतिक और सैन्य वास्तविकताएं भारत को लंबे समय तक जोख़मि में डाल सकती हैं।

पीओके की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि इसे भारत में शामिल करना देश की अर्थव्यवस्था पर एक भारी-भरकम बोझ डाल देगा। पीओके की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर है। वहाँ की जीडीपी प्रति व्यक्ति मात्र 1,200 डॉलर के आसपास है, जो भारत के राष्ट्रीय औसत (2,500 डॉलर) से भी कम है। भारत का अपना जम्मू-कश्मीर (जेएंडके) ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। अनुमानित रूप से, पीओके के 55-60 लाख निवासियों के लिए बुनियादी सुविधाओं पर प्रारंभिक निवेश ही 50,000 करोड़ रुपयए से अधिक का होगा। भारत, जो खुद वैश्विक मंदी और महंगाई से जूझ रहा है, इस क्षेत्र को संभालने में असमर्थ साबित होगा। आर्थिक पहलू के अलावा पीओके की जनसांख्यिकीय संरचना भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। 2017 की पाकिस्तानी जनगणना के अनुसार, पीओके की जनसंख्या लगभग 55 - 60लाख है। इनमें से 99 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम हैं, जिसमें पश्तून, बाल्टी और कश्मीरी समुदाय प्रमुख हैं। भारत पहले से ही कट्टरपंथी ताकतों से जूझ रहा है—नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और धारा 370 हटाने के बाद साम्प्रदायिक तनाव भी बरकरार हैं। पीओके के निवासियों को भारतीय नागरिकता देने पर वे सीमित संसाधनों वाले जेएंडके से बाहर निकलकर भारत के विभिन्न शहरों में फैल जाएंगे। इससे शहरी डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ जाएगा और वहाँ साम्प्रदायिक समस्याएं बढ़ेंगी। भारत में विलय के बाद ये समूह कट्टरपंथी राष्ट्र विरोधी संगठनों से जुड़ सकते हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां बढ़ेंगी। यह न केवल हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण को तेज करेगा, बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन को भी जन्म देगा। जनसांख्यिकीय विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में भारत का जनसंख्या संतुलन 20 वर्षों में 15 प्रतिशत तक बदल सकता है, जो भविष्य में राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रीय एकता पर संकट का कारण बनेगा।

पीओके के भारत मे विलय से सैन्य और सुरक्षा जोखिम भी कम नहीं होंगे। पीओके क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ और अशांत पहाड़ी इलाका है। इसका भूभाग अपनी दुर्गम भौगोलिक स्थिति और वर्तमान भू-राजनीतिक हालात के कारण एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बना रहेगा। इस क्षेत्र को स्थिर रखने के लिए एक स्थायी और विशाल सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता होगी। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार, पीओके को नियंत्रित करने के लिए भारत को अतिरिक्त एक लाख सैनिक तैनात करने पड़ेंगे, जिसका वार्षिक खर्च 30,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। वर्तमान में, भारत की सेना पहले से ही नियंत्रण रेखा पर तीन लाख सैनिकों के साथ व्यस्त है, और पीओके लेने पर यह एक अंतहीन आतंकवाद और युद्धक्षेत्र बन जाएगा।

बढ़ा हुआ सैन्य बोझ न केवल बजट को प्रभावित करेगा, बल्कि मानवीय हानि भी बढ़ाएगा। भारत की सैन्य क्षमता को फैलाने से पूर्वी लद्दाख (चीन सीमा) पर ध्यान कम होगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक होगा। यह मानने का भी कोई कारण नहीं है कि पीओके की आबादी का एक हिस्सा विलय का विरोध नहीं करेगा। भारतीय सेना और अर्ध-सैन्य बलों को न केवल बाहरी घुसपैठ, बल्कि एक नए आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। पीओके को लेने का सबसे बड़ा जोखिम भू-राजनीतिक है। यह क्षेत्र चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का केंद्र है, जो ग्वादर बंदरगाह से गिलगित तक फैला है। चीन ने यहां 60 बिलियन डॉलर निवेश किया है, और भारत का हस्तक्षेप बीजिंग को उकसाएगा।

पीओके लेने के लिए भारत की सैन्य कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय समुदाय आक्रामकता मानेगा। भारत की वर्तमान वैश्विक छवि—जो जी-20 और क्वाड से मजबूत हुई है—को ठेस पहुंचेगी। ज़ाहिर है, पीओके को वापस लेना भावुकता से प्रेरित है। पीओके का विलय केवल एक क्षेत्रीय विस्तार का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी गंभीर जोखिमों से भरा एक जटिल मुद्दा है। इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था पर एक नया, लंबे समय तक रहने वाला बोझ पड़ सकता है और देश की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक रूप से भी व्यावहारिक नहीं लगता।

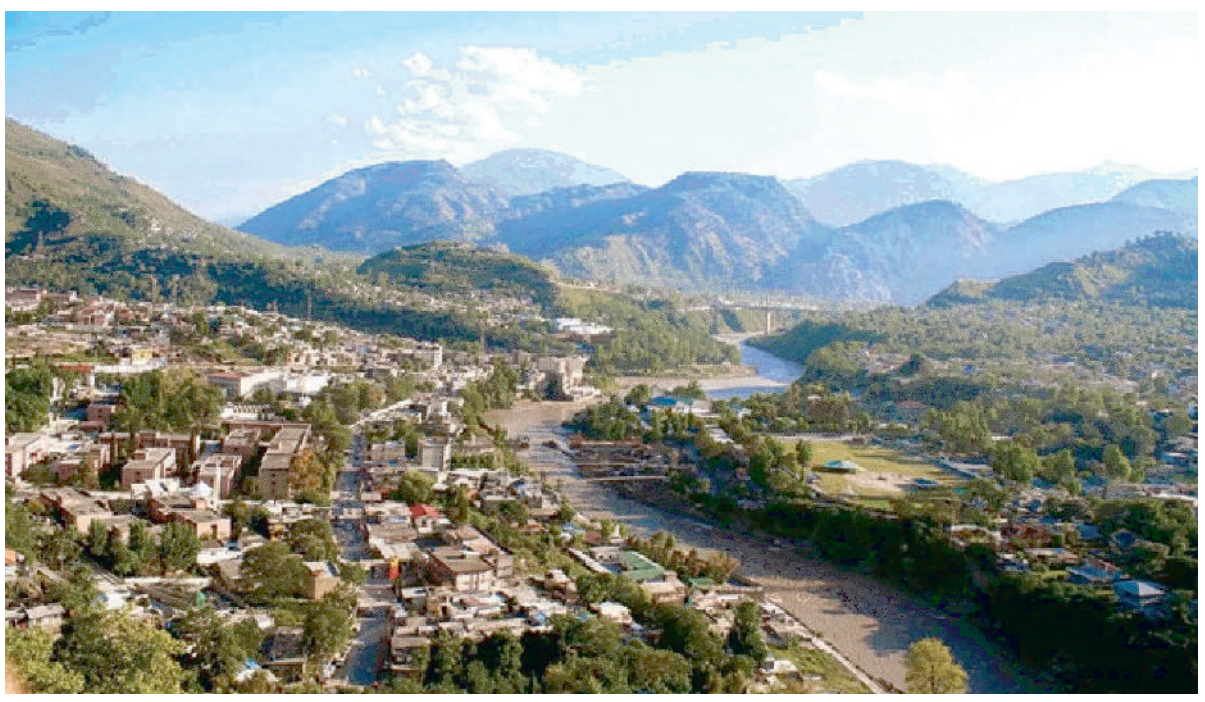

महिलाओं और बेटियां की कम या घटती संख्या

विजय गर्ग

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि देश में वर्ष 2022 में शिशु हत्या के 63 मामले दर्ज किए गए, जिनमें : महाराष्ट्र में सबसे अधिक 25 मामले । कन्या शिशु हत्या 1 के विशिष्ट आंकड़े अलग से नहीं दिए गए। यह संख्या वास्तविकता से बहुत कम हो सकती है, क्योंकि कई मामले उपेक्षा के कारण भुखमरी बता कर दर्ज नहीं होते। असल में कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं, क्योंकि गर्भपात के सभी मामले प्रायः दर्ज नहीं होते...

यह एक विचित्र विडंबना है कि पिछले कई दशकों से लगातार स्त्री-पुरुष अनुपात में बढ़ती खाई को लेकर चिंता जताई जाती रही है। इसे रोकने के लिए तमाम जागरूकता अभियानों से लेकर सरकारी कार्यक्रम भी चलाए गए। मगर आज भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कम या घटती संख्या के प्रति चिंता का स्तर एक ही जगह थम गया लगता है। हालत यह है कि इसके एक मुख्य कारण के रूप में भ्रूण हत्या पर चर्चा होती है, उसे रोकने के लिए नियम-कायदे भी बनाए जाते हैं, लेकिन अब भी इसका सहारा लेकर बेटियों को दुनिया में आने से पहले ही रोक देते हैं। भारत में भ्रूण हत्या मानो आम बात । चली है। जन्म के बाद लड़कियों को लावारिस छोड़ने अथवा झाड़ियों में फेंकने की भी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। तमाम प्रयासों बाद भी भ्रूण हत्या और नवजातों की मौत को रोका नहीं जा सका है। जबकि देश में भ्रूण हत्या से लिंगानुपात लगातार बिगड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में सामाजिक असंतुलन बढ़ता ही जाएगा। भ्रूण हत्या ऐसी ई है, जिसके आंकड़े न केवल डरावने हैं, बल्कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति और समाज को झकझोरते भी हैं।

सरकार के आंकड़ों

आधार पर 'प्यू रिसर्च सेंटर' की एक रपट कहती है कि वर्ष 2000 से 2019 तक भारत में कम से कम 90 लाख भ्रूण हत्या हुई। इनमें 186.7 फीसद हिंदुओं (80 फीसद आबादी), 4.9 प्रतिशत सिखों (1.7 फीसद आबादी) और 6.6 फीसद मुसलिमों (14 फीसद आबादी) में दर्ज की गई। हालांकि बेटे को वरीयता देने में अब कमी आई है, फिर देश में गर्भपात जारी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 0-6 वर्ष आयु वर्ग प्रति एक हजार लड़कों पर 914 लड़कियां थीं। जबकि वर्ष 1991 में यह अनुपात 945 था। भारत में लिंग अनुपात की कोई अच्छी स्थिति नहीं है। स्पष्ट है कि यह भ्रूण हत्या की और ही इशारा करती है। लांसेट की रपट कहती है कि हर वर्ष 2.39 लाख अतिरिक्त बालिका मृत्यु से कम) दर्ज। मृत्यु (5 वर्ष कम) दर्ज की जाती हैं, जो मुख्य रूप से उपेक्षा और कुपोषण के कारण होती हैं।

वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि देश में वर्ष 2022 में शिशु हत्या के 63 मामले दर्ज किए गए, जिनमें : महाराष्ट्र में सबसे अधिक 25 मामले । कन्या शिशु हत्या 1 के विशिष्ट आंकड़े अलग से नहीं दिए गए। यह संख्या वास्तविकता से बहुत कम हो सकती है, क्योंकि कई मामले उपेक्षा के कारण भुखमरी बता कर दर्ज नहीं होते। असल में कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं, क्योंकि गर्भपात के सभी मामले प्रायः दर्ज नहीं होते। दूसरी ओर नवजात की मौत के मामले भी कम दर्ज होते हैं, क्योंकि इन्हें अक्सर मृत जन्म या प्राकृतिक मृत्यु के रूप दिखाया जाता है। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लिंग अनुपात में भारी असंतुलन है। यह स्थिति गंभीर है। उत्तराखंड में 2019 के दौरान 132 गांवों में तीन महीने तक एक भी कन्या का जन्म नहीं हुआ। सरकार बाकायदा कानून पारित कर भ्रूण परीक्षण प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके बावजूद हालात नहीं बदले। देश में हजारों क्लीनिक ऐसे हैं, जहां आज भी भ्रूण परीक्षण चोरी-छिपे चल रहा है। राज्य सरकारों के पास इतने

संसाधन नहीं हैं कि सभी क्लीनिकों पर नजर रखी जा सके। इसके लिए आम नागरिकों को जागरूक होना होगा और सरकार की मदद करनी होगी। उधर, लड़कियों को जन्म से पहले मारने की प्रथा अब वहां भी प्रचलित हो रही है, जो अब तक इससे बचे हुए थे जैसी खबरें आ रही हैं, अब जम्मू-कश्मीर में भी स्थिति चिंताजनक है। वहां का श्रीनगर शहर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की राह पर है। ऐसी ही स्थिति और भी कई शहरों की बन रही है।

लड़कियों के प्रति इस नकारात्मक सोच के गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। यह बेहद चिंता का विषय है। बार-बार गर्भपात से स्त्रियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। यदि लड़कियों की संख्या इसी तरह घटती रही, तो आगे चल कर महिलाओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ने का अंदेशा है। विवाह के लिए उनका अपहरण किया जाएगा, उनकी इज्जत पर हमले होंगे। ऐसे में यह एक गंभीर स्थिति होगी। कर लड़कियों की कम संख्या उनके सम्मानजनक जीवन जीने के अवसरों कुल मिला को कम कर देगी और उनसे जुड़ी कई कुप्रथाओं भी बढ़ावा देगी। वहीं कई सामाजिक अवधारणाओं के कारण जब वह दिन शुरू मां के गर्भ में यह संघर्ष उसके जीवन के एक बड़े हिस्से को निगल । जाता है इस दुनिया में जीने की इजाजत क्यों न हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि कन्या भ्रूण हत्या अब किसी दायरे में सिमटी नहीं रह गई है । । शहरी क्षेत्रों क्षेत्रों और महानगरों में रहने वाले अति आधुनिक

भले ही उसे

शिक्षित लोग भी गर्भ में ही बालिकाओं की पहचान करा कर उसे खत्म करने में करने में पीछे नहीं हैं। यह बेहद ही दुखद स्थिति है।

लड़कियों की संख्या घटने का एक कारण यह भी है कि सरकार के जनसंख्या नियंत्रण अभियानों में कई कमियां रही हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार ने दो से अधिक बच्चों वाले । माता-पिता को कुछ अधिकारों से वंचित कर दिया है। जैसे, तीन बच्चों की मां को की मां को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। यदि वह कर्मचारी है, तो है, तो कई तरह की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसका सीधा असर महिलाओं के प्रति सामाजिक धारणा और संकीर्ण होने के रूप में सामने आता है। यह दुखद सच है कि लड़कियों के अनुपात में गिरावट के कारण कई ग कई राज्यों में युवाओं को में कई गरीब इलाकों के निर्धन परिवारों को विवाह के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। ऐसी खबरें आम रही आम रहा है, जिनम की लड़कियों को खरीद कर शादी करने के बारे में चिंता जताई जाती है। दलालों के जरिए खरीद- -फरोख्त का यह सिलसिला दिनों-दिन बढ़ रहा है। यह निराशाजनक है कि इसे रोकने के लिए किसी भी स्तर पर ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा जा रहा है।

के लिए खतरा है, बल्कि समाज के संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। इसे । इसे रोकने के । के लिए हर परिवार को जागरूक करना होगा, ताकि वे बेटियों को समान अधिकार और सुरक्षा देने की अहमियत को समझ सकें। हमें हर घर तक यह संदेश पहुंचाना होगा कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि देश और समाज की ताकत हैं। हमें उनके जन्म का उत्सव मनाना होगा और उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। कोई दोराय नहीं कि भ्रूण हत्या से लिंगानुपात बिगड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में सामाजिक असंतुलन बढ़ जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि कन्या शिशु का स्वागत करें और उनका पालन-पोषण तथा शिक्षा सुनिश्चित करें। इस तरह की सोच से ही हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। हमें इस दिशा में एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि हर बेटी सुरक्षित माहौल में पल कर आगे बढ़ सके।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

कौशल का पाठ : विजय गर्ग

शिक्षा का मुख्य आधार पाठ्यक्रम होता है। सरकारें हर कुछ अंतराल पर पाठ्यक्रम के विषय में बदलाव करती हैं, तो इससे कई बार असमंजस की स्थिति बन जाती है। नई शिक्षा नीति 2020 में हमने संकल्प लिया था कि वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम पचास फीसद विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान कर देंगे । यह भी तय किया गया था कि इसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्ययोजना भी विकसित कर लेंगे। मगर ऐसा लगता है कि पाठ्यक्रम की राजनीति में हमारा कौशल कहीं खो गया। हम पिछले पांच वर्षों में इस पर चर्चा के बजाय इस तरह पाठ्यक्रम निर्माण के उधेड़बुन में उलझ गए कि किस विषय को हटाना है, कौन - सा विषय जोड़ना है और किस विषय से भविष्य का मतदाता तैयार होगा।

जब कौशल की बात की जाती है या किसी व्यावसायिक शिक्षा की बात होती है, तो हमारे पाठ्यक्रम निर्माता यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि इस तरह की कोई मांग कहीं से आती नहीं । जबकि वे इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाते कि पाठ्यक्रम में जो विषय निर्धारित किए जाते हैं, उसकी मांग या आवाज कहां से आई है ? व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होने के पीछे प्रमुख कारण और तथ्य यह है कि हम मुख्य रूप से कक्षा आठ से ऊपर के विद्यार्थियों के कौशल की बात ही नहीं कर पाते । व्यावसायिक शिक्षा न मिल पाने के कारण अधिकतर विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति अरुचि रहती है, जिससे बीच में पढ़ाई छोड़ने की नौबत भी आती है। हमारे पाठ्यक्रम और प्रवेश के मानदंड भी व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से तैयार नहीं किए जाते। यही कारण है कि देश के अन्य लोगों के सापेक्ष 'मुख्य धारा की शिक्षा' या '

अकादमिक शिक्षा से विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के विषयों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए हमारी शिक्षा नीति में सीधे-सीधे कौशल के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के रास्ते पूरी तरह बंद हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के अनुमान के अनुसार, उन्नीस से चौबीस आयुवर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत कम, मात्र पांच फीसद लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में बावन फीसद, जर्मनी में पचहत्तर फीसद और दक्षिण कोरिया में तो छियानबे फीसद ने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की। भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता से रेखांकित किया जाना चाहिए। सरकार और शिक्षाविदों

को पाठ्यक्रम की राजनीति छोड़कर व्यावसायिक शिक्षा को पीछे धकेलने की प्रवृत्ति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

कौशल को पाठ्यक्रम में शामिल करने से पहले और व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के लिए हमें एक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्थानीय परिवेश और मांग के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। हम पाठ्यक्रम एक जैसा पढ़ा सकते हैं, लेकिन कौशल विकसित करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्थानीय जरूरत, मांग और बाजार के अनुसार ही निर्धारित करना होगा । अन्यथा यह वैसा ही होगा, जैसा पाठ्यक्रम में राजनीति होती है। बाजार को समांतर रखते हुए हमें विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा देने पर विचार करना होगा ।

आने वाली भावी पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति से परिचित होना ही चाहिए, लेकिन भारतीय इतिहास की उतनी ही जानकारी हमारे विद्यार्थियों को होनी चाहिए, जो सच-सच लिखा गया है। इतिहास बदलने और परंपराओं को परोसने का काम सरकारों को पाठ्यक्रम की राजनीति से दूर रखना होगा। सवाल है कि अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो इससे हम कैसा ज्ञान और कैसी संस्कृति सिखाना चाहते हैं। यह जरूरी है कि बढ़ती आबादी और बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए आने वाली पीढ़ी को व्यावसायिक

कौशल के माध्यम से हुनरमंद बनाया जाए। आजादी के बाद 'हर हाथ को काम मिले, हर व्यक्ति को रोटी मिले', जैसे नारे हमने दिए थे, उसे विद्यार्थियों तक हम पहुंचा नहीं सके। इसलिए यह जरूरी है कि हमारा पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा से ओतप्रोत हो, ताकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी अपनी रुचि का व्यवसाय प्रारंभ कर सके। विद्यार्थी परिवार पर बोझ न बने, बल्कि परिवार, समाज और देश के आर्थिक विकास में सहयोगी बन सके। यह सब माध्यमिक शिक्षा से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही संभव है।

शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार की शिक्षा देना भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। पूरे इतिहास में दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय के साक्ष्य और ' अध्ययन से पता चलता है कि सर्वोत्तम शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया जहां अनुसंधान और ज्ञान सर्जन की मजबूत संस्कृति रही है, वही विश्वविद्यालय श्रेष्ठ साबित हुए हैं। नई शिक्षा नीति में विभिन्न विषयों में अनुसंधान और भारतीय ज्ञान सर्जन की परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल करने और दुनिया की अर्थव्यवस्था में अनुसंधान तथा नवाचार का नेतृत्व करने के लिए हमें उसकी गुणवत्ता को भी देखना होगा। उच्चतर शिक्षण के तहत गुणात्मक शोध की मानसिकता को मजबूत करने की जरूरत होनी चाहिए । हमारा कौशल वैज्ञानिक और चिंतनशील अनुसंधान को मान्यता देने और उच्च अनुसंधान को स्थापित करने से ही संभावनाएं विकसित करेगा, न कि पाठ्यक्रम में राजनीति से ।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सभ्य समाज के लिये शर्म की बात

विजय गर्ग

बेटियों की साक्षरता में वृद्धि और कामकाजी क्षेत्र में लगातार उनकी बढ़ती भूमिका के बावजूद यदि दहेज उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि होती है, तो यह शर्मनाक स्थिति ही कही जाएगी। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की वह रिपोर्ट चौंकती है कि साल 2023 के दौरान देश में दहेज उत्पीड़न की घटनाओं में 14 फीसदी मामले ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इस वर्ष के दौरान दहेज के कारण देशभर में 6,100 महिलाओं की मौत दर्ज की गई है। 21वीं सदी को ज्ञान की सदी कहा जा रहा है और हम रूढ़िवादी सोलहवीं सदी में जी रहे हैं। लड़कियों के साथ यदि परिवार व्यवस्था में भेदभाव होता है और भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो उसके मूल में भी दहेज का अभिशाप ही है। लगातार खर्चीली होती उच्च शिक्षा व्यवस्था में बेटियों की शिक्षा पर बड़ा खर्च करने के बाद यदि मां-बाप को दहेज देना पड़ता है तो यह शर्मनाक स्थिति है। हालांकि, पिछले कुछ समय से पारिवारिक विवाद व अन्य कारकों को दहेज का मामला बनाने के कुछ मामले अदालतों की चिंता का भी विषय रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद समाज में दहेज के लिये उत्पीड़न की घटनाएं कटु सत्य है। यह भी एनसीआरबी की रिपोर्ट का यथार्थ है कि देश में हर रोज दहेज के लिये हत्याएं दर्ज हो रही हैं। बेटियों को पढ़ाने तथा सरकारों द्वारा उनके सशक्तीकरण के तमाम प्रयासों के बावजूद दहेज का दानव यदि अट्टहास कर रहा है तो यह हमारे समाज की असफलता ही कही जाएगी।

निस्संदेह, हमारे समाज में सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। एक समय नारा लगाया जाता था कि दुल्हन ही दहेज है। इस नारे को हकीकत बनाने की जरूरत है। कहीं न कहीं इस संकट के मूल में पितृसत्तात्मक सोच भी जिम्मेदार है। जिसमें स्त्रियों को वाजिब हक न देकर उन्हें कमतर आंका जाता है। इस बात पर वितचार किया जाना चाहिए कि दहेज प्रथा उन्मूलन के लिये सख्त कानून होने के बावजूद इस कुप्रथा पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। आखिर क्यों दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत मामले लगातार बढ़ रहे हैं। समाज में साक्षरता वृद्धि और जागरूकता अभियानों के बावजूद स्थिति जस की तस है। विडंबना यह है कि दहेज उत्पीड़न के ज्यादातर मामले बड़े हिंदी प्रदेशों में सामने आए हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और फिर बिहार दूसरे नंबर पर है। ये हजारों मामले समाज में स्त्रियों की विडंबनापूर्ण स्थिति को ही दर्शाते हैं। समाज में उपभोक्तावादी सोच के चलते भी दहेज की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। हमें विचार करना होगा कि समाज में दहेज के संकट की जड़ों पर कैसे प्रहार किया जाए। राष्ट्र का विकास तब तक एकांगी ही रहेगा, जब तक आधी दुनिया को समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता। दहेज के मामलों में न्याय भी शीघ्र देने की आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि वे समाज में सम्मानजक ढंग से बिना किसी पर निर्भर रहकर जीवनयापन कर सकें।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

कहानी : दस का नोट

विजय गर्ग

उन दिनों मैं संगीत सीख रही थी। दिनभर घर के कामकाज में फंसी, शाम के वक्त फुर्सत पाती तो आत्मा की तारें टुनक रही होतीं। लगता, कौन-सा वक्त हो कि मैं उड़कर संगीत की दुनिया में पहुंच जाऊं। अभी ही तो ज़िंदगी ने थोड़ी-सी फुर्सत दी थी, सांस लेने की। बच्चे कुछ अपने लायक हो गए थे और साईं भी मेहरबान था। घर की जिम्मेदारियों में से चार घंटे टिककर रियाज़ करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। यदि कभी सब काम निबटाकर रियाज़ के लिए बैठ भी जाती, तो कोई न कोई मिलने वाला ही आ धमकता... कभी जल रही दाल-सब्ज़ी की गंध ही मुझे संगीत के सागर में से बाहर उछाल देती।

सो, मैं अपना रियाज़ सुबह से ही स्टोव की आवाज़ में षड्ज का सुर मिलाकर शुरू करती। रसोई बनाते, कपड़े धोते, प्रेस करते, सीते-पिरोते, हर आवाज़ के साथ, हर ताल के साथ मिलकर मैं मनकों की भांति संगीत की माला में पिरोई हुई-सी इधर-उधर घूमती-फिरती। बेख़ुदी का ऐसा आलम था कि कॉलेज जाते हुए रिक्शे में या बस में लगातार मेरी चेतना की पतंग सुर की डोर में बंधी खुले आसमानों में उड़ती रहती और मुझे पता ही न चलता, किस वक्त घर से कॉलेज पहुंच जाती और वहां से कब वापस घर भी लौट आती।

चार बजे मेरी क्लास शुरू होती थी और घर से इतनी दूर जाने के लिए रिक्शा में बहुत देर लगती। कभी-कभार सिटी बस मिल जाती, वह भी आधा घंटा लगा देती, पर उसका भरोसा भी तो नहीं होता था। कई बार इंतज़ार करते-करते कॉलेज में बहुत देर से पहुंचती और पाठ मिस हो जाता, जो मुझे बहुत अखरता।

उस दिन घर से निकलने में कुछ विलंब हो गया था। पहले दिन ही नया राग 'मधुवंती' शुरू हुआ था। उसके आकार और स्वरूप के आलापों में मैं सुबह से ही डुबकियां लगा रही थी। राग के लोर में कुछ काम याद रखते हुए और कुछेक को बिसारते हुए जब मैं तेज़ कदमों से घर से निकलने लगी तो दिल में घबराहट-सी हो रही थी कि कॉलेज देर से पहुंचने पर कहीं राग के बेसिक सुर और उतार-चढ़ाव से वंचित ही न रह जाऊं।

अभी 'भाइये की डेरी' से भी पहले थी कि अचानक देखा, सड़क पर एक नोट मुड़ा-तुड़ा पड़ा था। मैंने उठाकर उसे सीधा किया। रंग-बिरंगा दस का नोट था। मैंने अपने आगे-पीछे देखा, कोई भी पास-दूर से देख नहीं रहा था। मैंने नोट को झट से पर्स में डाल लिया।

यद्यपि नोट उठाते हुए मुझे किसी ने देखा नहीं था, फिर भी पसीने की बूंदें मेरे माथे पर उभर आईं और लगा मानो अभी कोई पीछे से आवाज़ लगाकर कहेगा, 'मेहरबानी करके नोट मुझे वापस कर दो। मैंने तो यूं ही मज़ाक में फेंका था।' कभी लगता कि बहुत सारे बच्चों का एक ज़ोरदार ठहाका गूंजेगा और शर्मिंदगी में मुझे धरती भी राह नहीं देगी। मैंने अपने कदम और तेज़ कर लिए। बेचैनी की एक लहर ने मुझको सुरों के समंदर से बाहर उछाल दिया।

सामने ही एक रिक्शा खड़ा था। मैंने चलने के लिए पूछा। उस ज़माने में गुमटी से बड़े चौराहे तक अमूमन बारह आने दिया करती थी। किराया ज़रूर पहले ही तय कर लेती थी। इन रिक्शा वालों से भी बड़ा डर लगता है। टकेभर के आदमी मिनट भर में अच्छे-भले शरीफ़ आदमी की इज़्ज़त उतारकर रख देते हैं। ऐसी जगह पर जाकर ऊंचा-नीचा बोलेंगे कि सुनने वाले यही समझें कि सवारी ने ही ज़रूर बेइंसाफ़ी की होगी और ग़रीब का हक़ मारा होगा। यही सोचकर मैंने उससे पैसों के बारे में पूछा।

'सवा रुपया लगेगा।' उसने अजनबी-सी नज़रों से देखते और सीट पर कुछ संवरकर बैठते हुए जवाब दिया।

'अरे भैया, रोज़ के आने-जाने वाले हैं। रोज़ साठ पैसे में जाते हैं।'

मैंने झूठ बोलते हुए उससे रियायत करने का वास्ता दिया, पर वह टस से मस न हुआ।

'छाती के बल सवारी को ढोना पड़ता है। घाम के मारे हड्डियां पिघल रही हैं... कोई आपसे हराम के पैसे नहीं मांग रहे।'

वह तो और भी चौड़ा हो रहा था। उस वक्त आगे-पीछे दूसरा कोई रिक्शा भी तो दिखाई नहीं दे रहा था और वह शायद मेरी मजबूरी समझ गया था।

मैंने बमुश्किल उसको एक रुपये पर राज़ी किया। साढ़े तीन का समय तकरार में ही हो चला था।

रिक्शा में मैं बैठ तो गई, पर नोट ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कभी लगता, किसी छोटे बच्चे को मां ने सौदा लाने के लिए दिया होगा। वह पतंगों के पेच देखता या किसी अन्य खेल में खोया नोट गिरा गया होगा और फिर सौदा लेकर पैसे देते समय नोट न पाकर वह कितना भयभीत हुआ होगा या रोने लगा होगा। शायद उसकी मां ने इस लापरवाही के लिए उसको पीटा भी हो। रोटी खाने को न दी हो। बच्चा बहुत मासूम और गरीब भी हो सकता था, सोचकर मेरा दिल बैठने लगा।

कभी लगता कि बहुत ज्यादा भागदौड़ में बीमार बच्चे का बाप धोती की सात तहों में लपेटा मुड़ा-तुड़ा यह नोट अनजाने ही सड़क पर गिरा गया होगा। डॉक्टर को पैसे देते समय उसके मुंह पर किस तरह का पीलापन छा गया होगा... उसकी ज़बान किस तरह थुथला गई होगी... उसकी आंखें कैसे फैल गई होंगी... उसका दिल किस तरह डूब गया होगा।

नोट उठाते समय तो सोचा था कि चलो, चार-पांच दिनों का रिक्शा-भाड़ा ही निकला, पर अब सोच रही थी कि कैसे इससे जान छुड़ाऊं। किसी ऐसे व्यक्ति को दे दूं जिसको सबसे अधिक इसकी ज़रूरत हो। वह इसे हराम का माल न समझे, बल्कि किसी अहम काम के लिए इस्तेमाल कर सके, शायद तभी मैं इस बोझ से मुक्त हो सकूं।

अपनी महरी की तरफ ध्यान गया। जमादारिन के बारे में सोचा। गरीबी की दलदल में धंसी पड़ी थीं, पर उन्हें इस तरह फ़िज़ूल के पैसे देकर मैं अपने एहसान का एक तगड़ा बोझ भी उनके सिर पर लादना नहीं चाहती थी और अपनी दरियादिली की नुमाइश भी नहीं करना चाहती थी। यह मेरी रूह को कुछ जंचा नहीं।

कभी मन हो कि सड़क पर फेंक दूं। भाड़ में जाए — कोई उठाए या न उठाए, पर फिर ख़याल आया, किसी ने उठाकर शराब ही पी छोड़ी, या फ़िज़ूल में ही फूंक दिया तो!

रिक्शा तेज़ी से भाग रहा था। गर्मी के दिनों में दोपहर के बाद सड़कें जो भड़ास छोड़ती हैं, वह पूरी तरह वातावरण को अपने में लपेट रही थी। रिक्शावाले के कानों के पीछे पसीना धार बनकर बहता, उसकी मैली फेंटों वाली कमीज़ को लगातार भिगो रहा था और कमीज़ पूरी तरह उसके बदन से चिपककर काली रंगत दे रही थी। गीली कमीज़ में से उसकी सारी पसलियां गिनी जा सकती थीं। निक्कर के पहुंचे आधे फटकर उसके घुटनों तक लटक गए थे। बूट की जगह उसने बोरी के टुकड़ों को तह करके रस्सी से पैरों पर लपेटकर बांध रखा था, ताकि टूटे हुए पैडल, जो कि धूप में गर्म हो गए थे, के सेक से पैरों को बचाया जा सके। पसीना उसकी टांगों, बांहों से लगातार बह रहा था, जिसकी कोई बूंद किसी वक्त सड़क पर भी चू जाती और प्यासी सड़क झट से उसे चाट जाती।

तीस-पैंतीस साल का होगा वह... मैंने अनुमान लगाया। शायद, चार-छह बच्चे भी होंगे ही... उसकी घरवाली उसके घर पहुंचते ही उसके हाथों और जेब की ओर देखती होगी कि कुछ दे तो वह आटा-दाल खरीदकर चूल्हा जलाए। शायद, इसके बच्चों के तन पर कपड़ा भी होता होगा या नहीं। उसका हांफता हुआ शरीर, फटे हुए कपड़े और इस तरह बहता पसीना देखकर लगा कि उससे अधिक इस नोट का कोई हकदार नहीं हो सकता।

कॉलेज पहुंचकर मैंने पर्स में से वही दस का नोट निकाला और साथ में एक रुपया और, दोनों को मिलाकर उसके हाथ में रख दिया। बग़ैर उसकी तरफ देखे मैंने तेज़ कदमों से फाटक पार किया और कुछ दूर अंदर जाकर पलटकर देखा तो वह हाथ में नोट पकड़े, मुंह खोले हक्का-बक्का सा होकर देख रहा था। मुझे अजीब-सा आनन्द और सुकून मिला।

नृत्य-घर में से छोटी बच्चियों के घुंघरुओं की छनकार और अलग-अलग कमरों से आती संगीतमयी धुनों से वातावरण रंगा पड़ा था। प्रिंसिपल साहब के कमरे में से मेरी सहपाठिनों की एक सुर में आलाप की आवाज़ आ रही थी। मैंने अभी ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखा ही था कि पीछे से चपरासी ने आवाज़ लगाकर नीचे आंगन की तरफ इशारा किया।

रिक्शेवाला हाथ में नोट पकड़े अजीब-सी नज़रों से मेरी ओर देख रहा था।

'गरीब हैं तो क्या, मेहनत की कमाई खाते हैं। हराम का माल हमें नहीं चाहिए।'

मैं नदी के उतराव में बह रही थी... नोट नीचे आंगन में डोल रहा था।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

नारी शक्ति का सवश्रेष्ठ उदहारण है करवा चौथ

रमेश सर्राफ धमोरा

करवा चौथ सभी विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक पत्नियाँ अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना पानी पिए और कुछ भी खाए व्रत रखना आसान नहीं है, लेकिन स्नेही पत्नियाँ अपने पति के प्रति पूरे प्रेम और सम्मान के साथ ये सभी रस्में निभाती हैं। यह त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत हर साल महिलाओं द्वारा अपने पतियों के लिए किया जाता हैं और यह न केवल एक त्यौहार है बल्कि यह पति-पत्नी के पवित्र रिश्तों का पर्व है। कहने को तो करवा चौथ का त्यौहार एक व्रत है लेकिन यह नारी शक्ति और उसकी क्षमताओं का सवश्रेष्ठ उदहारण हैं। क्योंकि नारी अपने दृढ़ संकल्प से यमराज से भी अपने पति के प्राण ले आती हैं तो फ़िर वह क्या नहीं कर सकती हैं। आज के नये जमाने में भी हमारे देश में महिलायें हर वर्ष करवा चौथ का व्रत पहले की तरह पूरी निष्ठा व भावना से मनाती है।

आधुनिक होते समाज में भी महिलायें अपने पति की दीर्घायु को लेकर सचेत रहती है। इसीलिये वो पति की लम्बी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखना नहीं भूलती है। पत्नी का अपने पति से कितने भी गिले-शिकवे रहें हो मगर करवा चौथ आते-आते सब भूलकर वो एकाग्र चित्त से अपने सुहाग की लम्बी उम्र की कामना से व्रत जरूर करती है। करवा चौथ शब्द करवा अर्थात मिट्टी का बर्तन और चौथ अर्थात चतुर्थी से मिलकर बना है। इस पर्व पर मिट्टी के करवे का विशेष महत्व होता है। सभी विवाहित महिलाएं पूरे वर्ष इस त्योहार की प्रतीक्षा करती हैं और इसकी सभी रस्मों को श्रद्धा के साथ निभाती हैं।

हमारा देश एक धर्म प्रधान देश हैं। यहां साल के सभी दिनो का महत्व होता है तथा साल का हर दिन पवित्र माना जाता है। भारत में करवा चौथ हिन्दुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चन्द्रमा दर्शन के बाद सम्पूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलायें करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। यह व्रत लगातार 12 अथवा 16 वर्ष तक हर वर्ष किया

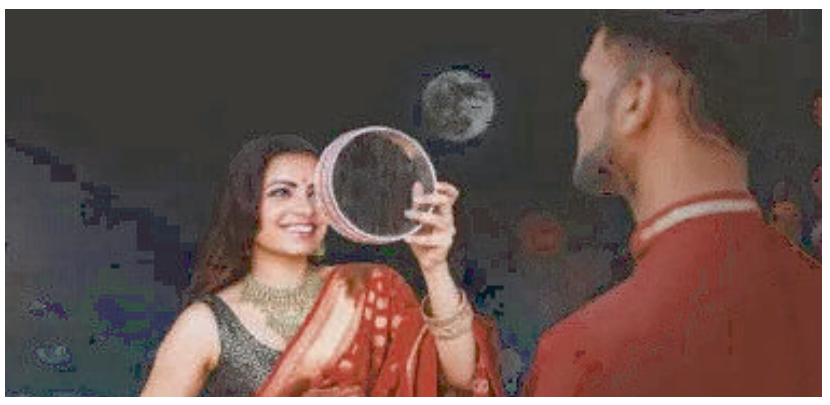

जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवनभर इस व्रत को कर सकती हैं।

किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। जो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं वे व्रत रखती हैं। बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी पर शिव-पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर नाल बांधकर ईश्वर का स्मरण कर स्थापित करें। पश्चात यथाशक्ति देवों का पूजन करें। करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। दिन में करवाचौथ व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें।

शास्त्रों के अनुसार पति की दीर्घायु एवं अखण्ड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचन्द्र गणेश जी की पूजा-अर्चना की जाती है। करवा चौथ में दिन भर उपवास रखकर रात में चन्द्रमा को अर्ध्य देने के उपरान्त ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथव्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं। लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चन्द्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। सायंकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्ध्य प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण, सुहागिन स्त्रियों व पति के माता-पिता को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। अपनी सासूजी को वस्त्र व विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद लें। यदि वे न हों तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट करें। इसके पश्चात स्वयं व परिवार के अन्य सदस्य भोजन करें।

कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी अर्थात उस चतुर्थी की रात्रि को जिसमें चंद्रमा दिखाई देने वाला है। उस दिन प्रातः स्नान करके अपने पति की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिनभर निराहार रहें। उस दिन भगवान शिव-पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करें। शुद्ध घी में आटे को सेंककर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर नैवेद्य हेतु लड्डू बनाएं। काली मिट्टी में शक्कर की चासनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी के अथवा तांबे के बने हुए अपनी सामथ्र्य अनुसार 10 अथवा 13 करवे रखें।

करवा चौथ के बारे में व्रत करने वाली महिलाएं कहानी सुनती है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रोपदी बहुत परेशान थीं। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा बहना इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकरजी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्ध्य देकर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने, चाँदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान-प्रदान किया जाता है। जो आपसी प्रेम-भाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएँ अपने सास-ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकरजी ने माता पार्वती को करवा चौथका व्रत बतलाया।

इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीनकाल में एक ब्राह्मण था। उसके चार लडके एवं एक गुणवती लडकी थी। एक बार लडकी मायके में थी। तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधिपूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही। कुछ खाया-पीया नहीं, पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी।भाइयों से न रहा गया उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी देखो बहन चंद्रमा निकल आया है। पूजन कर भोजन ग्रहण करो।

बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुःखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थीं। उनसे उसका दुःख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुःख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया कि तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया इसलिए यह कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियमपूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथव्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रोपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिन्दू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ व्रत करती हैं।

कहते हैं इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल-कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है। तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। भारत देश में चौथमाता का सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बरवाड़ा से चौथ का बरवाड़ा पड़ गया। यहां के चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीमसिंह चौहान ने करवायाथा।

(लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

सत्य, त्याग और ईमानदारी के प्रतीक हैं गोपबंधुः मनमोहन सामल

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वरः उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास न केवल उत्कल के, बल्कि पूरे विश्व के रत्न हैं। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कवि, लेखक और दैनिक समाचार पत्र सोसाइटी तथा सत्यवादी पत्रिका के संस्थापक थे। वे सत्य, त्याग और ईमानदारी के प्रतीक थे। ओडिशा के इस महान सपूत की 148वीं जयंती के अवसर पर, प्रदेश अध्यक्ष श्री मनमोहन सामल ने भुवनेश्वर के गोपबंधु चौक स्थित गोपबंधु की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर श्री सामल ने कहा कि उत्कलमणि गोपबंधु ने ओड़िया भाषा के विलुप्त होने का विरोध किया। उनका आह्वान था कि प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा है। भाषा राष्ट्र की आत्मा है। इसी प्रकार, जब वे कलकत्ता में अध्ययन कर रहे थे, तब वे ओड़िया प्रवासियों की दुर्दशा देखकर द्रवित हुए और उन्होंने ओडिशा श्रमिक संघ और सांध्य विद्यालय की स्थापना की। श्री सामल ने कहा कि पृथक ओडिशा प्रांत के निर्माण में उनका योगदान अद्वितीय है। इस अवसर पर विधायक बाबू सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सुदीप्त रॉय, भुवनेश्वर जिला अध्यक्ष निरंजन मिश्रा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जगन्नाथ प्रधान, प्रियदर्शी मिश्रा सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

भूबनेश्वर यूनिट में बुलडोजर का ढेर

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भुबनेश्वरः खारवेलनगर थाना क्षेत्र में आज बुलडोज़र चला। भुवनेश्वर महानगर निगम (बीएमसी) ने श्रेया चैक से मल्लिक कॉम्प्लेक्स तक सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण हटा दिया है। इसके साथ ही, सड़क के दोनों ओर जमा कूड़े के ढेर को भी हटा दिया गया है। बीएमसी ने कहा है कि इस क्षेत्र में तोड़फोड़ अभियान जारी रहेगा।दूसरी ओर, प्रभावित परिवारों ने अवैध कब्ज़ेदारों को बेदखल करने का विरोध किया है। वे इस बेदखली को अनुचित बताते हुए वहाँ से हट नहीं पा रहे हैं।

श्रेया चैक से लेकर मलिक कॉम्प्लेक्स, मालीशाही, एनएसी कॉलोनी आदि इलाके कूड़े से अटे पड़े हैं। चूँकि यहाँ कई कबड्डी की दुकानें हैं, इसलिए राज्य भर से कबड्डी का सामान यहाँ जमा रहता है। आधी से ज़्यादा ज़मीन पर कबड्डी दुकानदारों का कब्ज़ा है। दुकानदार सड़कों पर टूटे-फूटे सामान और कबड्डी का सामान जमा कर रहे हैं। जिससे यातायात में बाधा आ रही है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही, उन्होंने सड़क किनारे बने नाले पर भी अतिक्रमण कर लिया था। उन्होंने उस पर दुकानें खोलकर नाले को भर दिया था। कबड्डी दुकानदारों के अलावा, अन्य दुकानदारों ने भी सड़क की सुंदरता बिगाड़ी और रास्ते को संकरा और अतिक्रमण कर दिया। आज इन सभी को ध्वस्त कर दिया गया। बीएमसी के अधिकारी आज सुबह मौके पर पहुँचे और तोड़फोड़ अभियान शुरू किया। बुलडोज़र से दुकानों और सड़क किनारे बने अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया गया। यह देख इलाके के निवासियों ने विरोध किया। अंत में पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ जारी रही। कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखते हुए खारवेल थाने में पुलिस और बल के साथ बीएमसी प्रवर्तन दस्ता तैनात किया गया था। इलाके के निवासियों ने दावा किया है कि आज तोड़फोड़ के अंत तक लगभग 55 दुकानें ध्वस्त कर दी गई हैं। दूसरी ओर, प्रभावित परिवारों ने शिकायत की है कि बीएमसी ने तोड़फोड़ से पहले हमें कोई पूर्व सूचना नहीं दी। हमें कल रात दुकानें हटाने के लिए कहा गया था। वे आज सुबह आए और दुकानों को तोड़ दिया। यह अन्याय है। ऑल ओडिशा रोडसाइड शॉपकीपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रताप कुमार साहू ने कहा कि बीएमसी से मांग की गई थी कि जिन दुकानदारों को तोड़ा गया है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। बीएमसी ने सभी को फिर से बसाने का वादा किया है। अगर निवारण नहीं किया जाता है, तो हम सक्रिय रुख अपनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिया: असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करें, ओडिशा की छवि खराब नहीं करने दी जाएगी

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भुबनेश्वरः ओडिशा एक शांतिपूर्ण राज्य है। लेकिन कुछ समूह राज्य की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने वाले उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आज लोक सेवा भवन में राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद पुलिस महानिदेशक को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।कटक के हालात पर चर्चा के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। हालात में सुधार के साथ ही कर्फ्यू हटा लिया गया है और इंटरनेट सेवाएँ बहाल कर दी गई हैं। हालात हल्के भी हों, पुलिस को सतर्क रहना होगा और किसी भी हालत में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मौजूदा हालात में सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती और गश्त जारी रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारी विभिन्न समुदायों के नेताओं के साथ लगातार बातचीत करते रहें ताकि भाईचारे वाले शहर में सामाजिक सौहार्द की वापसी हो सके।इसी प्रकार, मुख्यमंत्री श्री माझी ने ब्रह्मपुर में वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय पीतावास पांडा की हत्या पर गहरा दुःख व्यक्त किया और हत्यारों को तुरंत पकड़ने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि दोषियों को न केवल गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उनके विरुद्ध यथासंभव कार्रवाई भी की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार प्रकाश मिश्रा, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सत्यव्रत साहू, पुलिस महानिदेशक वाई.बी. खुरानिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शाश्वत मिश्रा और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

"वाह री सरकार! 25 रुपए का दीवाली गिफ्ट, कर्मचारियों ने जताया धन्यवाद"

परिवहन विशेष न्यूज

मप्र के लाखों दैनिक वेतनभोगियों के साथ बड़ा मज़ाक, वेतन में 1 रुपए प्रतिदिन, महीने में सिर्फ 25 रुपए की बढ़ोतरी

प्रदेश के लाखों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सरकार ने इस बार ऐसा तोहफा दिया है, जिसे सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं, व्यंग्य झलक रहा है। श्रम आयुक्त द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन में सिर्फ एक रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। यानी महीने के लगभग 25 दिन काम करने वाले कर्मियों को सिर्फ 25 रुपए का दीवाली गिफ्ट मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह बढ़ोतरी सीपीआई इंडेक्स के अनुसार की गई है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि यह महंगाई के दौर में मज़ाक से ज़्यादा कुछ नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार मजदूरी में कम से कम 150 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि होनी चाहिए थी, ताकि वास्तविक महंगाई के अनुपात में राहत मिल सके। जानकारी के मुताबिक यह संशोधित वेतन दर 1 अक्टूबर 2025 से लागू की गई है, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। प्रदेश में करीब 10 लाख दैनिक वेतनभोगी इस निर्णय से प्रभावित होंगे, लेकिन सभी को यह वृद्धि नाम मात्र की लग रही है। वहीं कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार को "आभार" जताते हुए तंज कसा है —

"धन्यवाद सरकार, कम से कम हमें याद तो किया!"

दावा- सीपीआई इंडेक्स के अनुसार ही की है यह बढ़ोतरी

श्रमिकों से अन्याय बर्दाश्त नहीं

मप्र कर्मचारी मंच ने श्रम आयुक्त द्वारा दैनिक वेतन भोगियों के महंगाई भत्ते में किए गए इजाफे पर आक्रोश जाहिर किया है। कर्मचारियों के संगठन ने कहा कि रोजाना सिर्फ 1 रुपए का इजाफा किया गया। है। यह प्रदेश के सैकड़ों दैनिक वेतन भोगी एवं श्रमिकों के साथ छलावा है। नई दरों से अकुशल श्रमिक का वेतन 12125 से बढ़कर सिर्फ 12150 होगा। यही स्थिति अर्ध कुशल कुशल और उच्च कुशल श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के वेतन की है। यह वेतन हमें स्वीकार नहीं है। हमारी यह मांग है कि 1 अप्रैल 2025 से दैनिक वेतन भोगी एवं श्रमिकों के वेतन में न्यूनतम 1000 रुपए की वृद्धि की जाए। मध्यप्रदेश के 10 लाख से ज्यादा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन से जुड़ा बड़ा झटका लगा है। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाया जरूर है, लेकिन सिर्फ 1 रुपए रोजाना। यानी अब दैनिक वेतन भोगी को हर दिन 1 रुपए ज्यादा और महीने में करीब 30 रुपए ज्यादा मिलेंगे। श्रम आयुक्त ने 1 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए नई दरें लागू होंगी। सरकार ने यह बढ़ोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई इंडेक्स) के आधार पर की है। जनवरी से जून 2025 की औसत दर 414 रही, जबकि पिछली बार यह 413 थी। इसी 1 अंक के फर्क के कारण महंगाई भत्ते में 1 रुपए रोज का इजाफा किया गया है। जानकारों के मुताबिक, इतनी कम बढ़ोतरी पहले कभी नहीं हुई। एक्सपर्ट बोले- कम से कम 150 रुपए प्रतिदिन बढ़ना चाहिए था केवल एक रुपया बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। 1956 के भारतीय श्रम सम्मेलन के अनुसार, वेतन एक परिवार की जरूरतों पर आधारित होना चाहिए, जिसमें चार सदस्य माने जाते हैं। हर पांच वर्ष में वेतन का पुनरीक्षण अनिवार्य है। सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 प्रतिमाह तय किया था। मप्र में अप्रैल 2024 से लागू दरों को देखें तो महंगाई के अनुसार प्रतिदिन 150 की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 1 रुपए प्रतिदिन बढ़ाया है।

बिहार में महागठबंधन की बड़ी समस्या क्या है

राजेश कुमार पासी

चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. 14 नवम्बर को बिहार के अगले मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा। यह चुनावी युद्ध दो गठबंधनों के बीच होने वाला है लेकिन सवाल यह है कि कौन सा गठबंधन कितना तैयार है। 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। एनडीए को महागठबंधन से सिर्फ 12000 ज्यादा वोट हासिल हुए थे। जहां एनडीए को 37.26 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को 37.23 प्रतिशत वोट मिले थे। एनडीए में जेडीयू कमजोर कड़ी साबित हुआ था तो महागठबंधन में कांग्रेस कमजोर कड़ी बनी थी। एनडीए ने इस कमजोरी को पहचाना कि जेडीयू को नुकसान पहुंचाने का काम चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने किया है। वास्तव में एलजेपी ने खुद तो कुछ हासिल नहीं किया था लेकिन जेडीयू को लगभग 20 सीटों का नुकसान पहुंचाया था। इस कमजोरी को दूर करते हुए एनडीए ने एलजेपी को गठबंधन में शामिल कर लिया है।

महागठबंधन की कमजोरी दूर होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए 70 सीटें दी गई थी लेकिन उसे सिर्फ 19 सीटों पर ही सफलता मिली। अगर कांग्रेस को कम सीटें दी गई होती तो 2020 में महागठबंधन की सरकार बन सकती थी। तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था कि कांग्रेस के कारण महागठबंधन सत्ता हासिल करने में सफलता नहीं मिली है। कांग्रेस इस बार भी ज्यादा सीटें पाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि चुनाव की घोषणा हो गई है और पहले चरण का मतदान 6 नवम्बर को होना है लेकिन अभी तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दूसरी बात सीटों का बंटवारा जल्दी होने की उम्मीद भी नहीं है। अगर समय पर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो ये उसकी चुनावी संभावनाओं को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अजीब बात है कि राहुल गांधी बिहार में चुनावी माहौल तैयार करने के लिए वोट यात्रा निकाल रहे थे लेकिन ऐन चुनाव के वक्त वो विदेश यात्रा पर चले गए। अब वो यात्रा से वापिस आ गए हैं लेकिन सीटों के बंटवारे के लिए कब आरजेडी से बात करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है।

राहुल गांधी की यात्रा में महागठबंधन ने पैसा और ऊर्जा तो बहुत खर्च किया लेकिन उसका चुनाव पर असर होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। वोट चोरी का आरोप लगाने वाली यात्रा के बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी यात्रा निकाली थी लेकिन उनकी यात्रा में वोट चोरी का मुद्दा ही गायब हो गया। इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव मानते हैं कि यह मुद्दा चुनाव में फायदा देने वाला नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ चुनाव में हारने के बाद अपनी झेंप मिटाने के लिए किया जा सकता है। अजीब बात है कि जो गठबंधन वोट चोरी का आरोप लगा रहा था, उसके नेता चुनाव की घोषणा के बाद जीत का दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब भाजपा वोट चोरी करके चुनाव जीतती है तो गठबंधन के नेता जीत का दावा किस आधार पर कर रहे हैं।

जहां एनडीए अपनी जीत पक्की करने के लिए चिराग पासवान को साथ ले आया है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन को अपने साथी संभालने में ही दिक्कत आ रही है। पिछली बार दोनों गठबंधनों को लगभग बराबर वोट मिले थे जबकि चिराग पासवान लगभग 5-6 प्रतिशत वोट ले गए थे। अब यह तय है कि ये वोट एनडीए के खाते में जाने वाले हैं तो एनडीए को बड़ी बढ़त हासिल हो गई है। महागठबंधन ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे कहा जा सके कि पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होने जा रही है। एक बड़ी समस्या गठबंधन की यह भी है कि अभी तक वहां नेता की घोषणा नहीं हुई है। सबको पता है कि गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ही होंगे लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं माना है। दूसरी तरफ भाजपा ने घोषणा कर दी है कि एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। चुनाव से सिर्फ एक महीने पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अस्पष्टता होना नुकसानदायक है। बिहार में 85 साल बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई है जिसके बाद पार्टी महासचिव नासिर हुसैन ने दावा किया कि कांग्रेस जल्दी घोषित होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व करेगी। इसके दो मकसद हो सकते हैं. पहला तो यह कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना चाहती है ताकि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ सके। दूसरा यह हो सकता है कि वो गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने के लिए हासिल करना चाहती हो। पहला मकसद तो अच्छा है लेकिन दूसरा मकसद खतरनाक है।

कांग्रेस बिहार चुनाव में एक बड़ी गलती करने की कोशिश कर रही है, जो महागठबंधन को बहुत भारी पड़ने वाली है। वो बिहार चुनाव में राहुल गांधी को गठबंधन का नेता बनाना चाह रही है। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने यात्रा निकाल कर यह साबित करने की कोशिश की है कि वो ही गठबंधन के नेता हैं। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद नासिर हुसैन का बयान भी यही बता रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। सच्चाई सबको पता है कि गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं तो ऐसा संदेश क्यों दिया जा रहा है। भाजपा तो पहले ही बिहार चुनाव को मोदी केंद्रित बनाना चाहती है क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सेहत को बड़ा मुद्दा बना दिया है। गठबंधन का हित इसी में है कि बिहार चुनाव नीतीश बनाम तेजस्वी बने रहे लेकिन कांग्रेस की कोशिश इस चुनाव को मोदी बनाम राहुल बना सकती है। वैसे भी चुनावी सर्वे बता रहे हैं कि बिहार चुनाव में मोदी बड़ा मुद्दा हैं और अब कांग्रेस की यह कोशिश इस मुद्दे को और बड़ा बना सकती है।

वास्तव में बिहार चुनाव में मोदी इसलिए बड़ा मुद्दा हैं क्योंकि उनकी लोक कल्याणकारी योजनाओं का जनता को बड़ा फायदा मिला है। केन्द्र सरकार की योजनाओं की सफलता के कारण बिहार में भाजपा का बड़ा वोट बैंक तैयार हो गया है। जाति-संप्रदाय की राजनीति वाले बिहार में इन योजनाओं का फायदा सभी समुदायों को बिना किसी भेदभाव के मिला है, इसलिए मोदी के समर्थन में एक ऐसा वोट बैंक तैयार हो गया है, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर भाजपा को वोट देता है। पिछले पांच सालों में आरजेडी अपने मुस्लिम-यादव वोट बैंक में कुछ नया नहीं जोड़ पाई है लेकिन केंद्र की योजनाओं के कारण उसके वोट बैंक में सेंध लग सकती है। विशेष रूप से महिलाएं चुपचाप एनडीए के समर्थन में वोट कर सकती हैं। नीतीश सरकार ने भी ऐन चुनावों के वक्त बिहार की जनता को लुभाने के लिए न केवल योजनाओं की घोषणा की बल्कि उनका फायदा भी जनता को दे दिया है। चुनाव के समय सत्ताधारी दल के वादे पर जनता ज्यादा भरोसा इसलिए नहीं करती है क्योंकि उसे लगता है कि जब वो सत्ता में रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में क्या करेंगे। जब सत्ताधारी दल की सरकार से जनता को बड़ा फायदा मिलता है तो उसे उम्मीद हो जाती है कि आगे भी यह सरकार उनको फायदा देगी।

महागठबंधन के नेता बिहार की जनता से बड़े वादे कर रहे हैं लेकिन जनता उन पर कितना भरोसा करेगी, ये तो चुनाव परिणाम ही बतायेंगे। नीतीश सरकार ने चुनाव के वक्त अपनी योजनाओं से अपने वोट बैंक में बढ़ोतरी की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस के कारण गठबंधन की तरफ सवर्ण वोट बैंक आने की उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि गठबंधन को मुस्लिम आक्रामकता के साथ वोट करते हैं। राहुल गांधी की दलित-पिछड़ा राजनीति भी बिहार चुनावों को प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी अन्य पिछड़ी जातियों के बड़े नेता हैं। यादवों का डर दलित समाज को गठबंधन की तरफ जाने से रोकता है। तेजस्वी यादव की बड़ी समस्या अभी भी लालू यादव का जंगलराज बना हुआ है। भाजपा की सोशल मीडिया टीम बिहार की जनता को जंगलराज का डर दिखा रही है। समस्या यह है कि लोग लालू यादव का राज अभी तक नहीं भूले हैं। बिहार में जनता का बड़ा वर्ग नहीं चाहता है कि वो दिन दोबारा देखने पड़े, इसलिए यह मुद्दा तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा सकता है। औवेसी भी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि अपने विधायकों को तोड़ने का बदला लेना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है कि वो किसका ज्यादा नुकसान करेंगे।

मेरा मानना है कि युद्ध में दुश्मन के सामने जाने के पहले अपने दल की कमजोरियों को दूर कर लेना चाहिए। समस्या यही है कि गठबंधन अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा न केवल अपनी कमजोरियों पर काबू पा रही है बल्कि अपनी ताकत भी बढ़ा रही है। बिहार की राजनीति की अजीब बात यह है कि भाजपा और राजद लगभग बराबरी पर खड़े हैं, इसलिए नीतीश कुमार जिसकी तरफ होते हैं, वही जीत जाता है। भविष्य में क्या होगा, पता नहीं लेकिन आज का सच यही है कि नीतीश कुमार पूरी मजबूती से भाजपा के साथ खड़े हैं।

ओबीसी के हांथों विशेषकर 'यादवों' के हाथ होगी बिहार में सरकार बनाने की "मास्टर की"

डॉ. राजकुमार यादव, राष्ट्रीय संयोजक – ओबीसी अधिकार मंच

>"बिहार की राजनीति की धड़कन अगर किसी समुदाय में बसती है, तो वह यादव समाज है — जिसने सत्ता को दिशा दी, संघर्ष को स्वर दिया और सामाजिक न्याय की मशाल जलाए रखी।"

बिहार की सत्ता का केंद्र – यादव समाज

बिहार की सामाजिक रचना में यादव समाज की भूमिका सिर्फ संख्यात्मक नहीं, बल्कि निर्णायक है।

राजनीति से लेकर समाज तक, गाँव की चौपाल से लेकर विधान सभा की चौखट तक — यादवों का अस्तित्व हर स्तर पर गूंजता है।

आज बिहार की राजनीति में कोई भी दल तब तक सत्ता की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, जब तक ओबीसी समाज उसका साथ न दे।

जनगणना और राजनीतिक अध्ययनों के अनुसार, बिहार में सिर्फ यादवों की जनसंख्या ही लगभग 14% है — लेकिन प्रभाव 40% से अधिक सीटों पर निर्णायक है और पूरा ओबीसी समाज के साथ नजारा ही कुछ और होगा1

यह वही वर्ग है जिसने वर्षों से नेतृत्व की मशाल थामे रखी है, अन्य पिछड़ा वर्गों ने एकजुटता दिखाकर चुनाव प्रभावित किया है, और गरीबों, किसानों, श्रमिकों की आवाज़ बनकर उभरा है।

राजनीति का इतिहास यादवों के योगदान से भरा है

बिहार के सामाजिक न्याय आंदोलन की बुनियाद विशेषकर यादव समाज ने रखी थी।

डॉ. लोहिया के विचारों से प्रेरित इस वर्ग ने राजनीति को "अमीरी बनाम ग़रीबी" की बहस से निकालकर "समान अवसर और सम्मान" के रास्ते पर मोड़ा।

यादव व अन्य ओबीसी नेताओं के नेतृत्व में यह समाज सत्ता के केंद्र में पहुँचा, और आज भी उनकी राजनीतिक चेतना बिहार की नसों में बह रही है।

लेकिन अब समय बदल चुका है –

नए युग के यादव युवा शिक्षित, जागरूक और तकनीकी दृष्टि से सक्षम हैं।

वे अब सिर्फ वोटर नहीं, नीति-निर्माता और सत्ता-साझेदार बनना चाहते हैं।

2025: निर्णायक वर्ष — ओबीसी की एकता से तय होगी सत्ता

2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन की पुनर्स्थापना का अवसर है।

आज जब आरक्षण, रोजगार और ओबीसी प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तब यादव समाज का नेतृत्व फिर से आवश्यक हो गया है।

ओबीसी अधिकार मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. राजकुमार यादव ने स्पष्ट कहा है –

>"यह समय ओबीसी समाज को एकजुट होकर अपनी भूमिका तय करने का है न की जाती विवाद मे समय नष्ट करने का -सभी धड़े आगे बढ़ें व नेतृत्व का सम्मान करें"

अब हम केवल सरकार बनाने की 'मास्टर की' नहीं रहेंगे —

हम ही वह शक्ति बनेंगे जो बिहार में न्यायपूर्ण शासन की नींव रखेगी।"

ओबीसी एकता की नई धारा

यदि यादव, कुर्मी, कोइरी, मल्लाह, निषाद, पासवान, धानुक, बनिया जैसे अन्य पिछड़े वर्ग एकजुट होकर "ओबीसी मोर्चा" के रूप में सामने आते हैं —

तो बिहार की सत्ता संरचना पूरी तरह बदल जाएगी।

आज ओबीसी वर्ग बिहार की 60% आबादी है — यह सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ताकत का मेरुदंड है।

यादव इस शक्ति के केंद्र हैं, जो सबको जोड़ सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, और सत्ता को समाज के हित में मोड़ सकते हैं।

नई पीढ़ी का संकल्प — शिक्षा, रोजगार और सम्मान

ओबीसी समाज का युवा अब जातीय सीमाओं से आगे बढ़कर विकास, रोजगार और सम्मान की राजनीति चाहता है।

वह चाहता है कि उसकी भागीदारी सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि नीति और प्रशासनिक स्तर पर भी सुनिश्चित हो।

सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन जब तक पिछड़ों की आवाज़ नीति-निर्माण के केंद्र में नहीं होगी, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा।

और यह बदलाव तभी आएगा जब ओबीसी समाज आपसी व अल्पकालिक कलह को भुला अपने नेतृत्व में एकजुट रहेगा।

निष्कर्ष – बिहार की राजनीति की "मास्टर की" ओबीसी समाज के हाथ

बिहार की सियासत का ताला हर बार ओबीसी विशेषकर यादव की "मास्टर की" से ही खुला है।

यह वर्ग न तो किसी का पिछलग्गू है, न किसी का मोहरा।

यह वह शक्ति है जिसने अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखा है, और अब शासन में अपनी निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है।

"जो बिहार को समझता है, वह ओबीसी व विशेषकर यादवों की ताकत को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।

आने वाला बिहार उन्हीं के नेतृत्व में नया व अमिट इतिहास नए दमखम व कलेवर से लिखेगा।"

पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन द्वारा एक भव्य रक्त दान कैंप का आयोजन किया

अमृतसर, 8 अक्टूबर साहिल बेरी

केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ अजय गुप्ता ने आज गुरुपर्व के पावन अवसर पर पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन द्वारा एक भव्य खून दान कैंप का आयोजन में मुख्य तौर पर भाग लिया। विधायक डॉ गुप्ता ने बताया कि इस सेवा अभियान को सफल बनाने में पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ शर्मा, उपाध्यक्ष विशाल , चेयरमैन विवेक और सचिव रूपेश ने अपना योगदान दिया।

इस अवसर पर डिप्टी मेयर अनीता रानी के पुत्र तरुण बीर कैंडी , वार्ड प्रभारी विशाल गिल , समाजसेवी विक्की चीदा , एससी विंग संयोजक राजेश मल्होत्रा , सुनील पहलवान , ब्लॉक प्रभारी अजय नोएल और चिराग ने भी शिविर की प्रतीकात्मक सफलता में अपना योगदान दिया।

विधायक डॉ गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से रक्तदान का संदेश हर कदम तक पहुँचाया गया और लोगों को स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि आपको विश्वास दिलाते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार हमेशा आपके साथ है।

स्लाइट के छात्रों का अत्यधिक प्रतिष्ठित कंपनियो में रिकॉर्ड संख्या में चयन

संस्थान के 90% से अधिक छात्रों की विभिन्न इंजीनियरिंग शाखाओं में हुई नियुक्ति

लोंगोवाल,9 अक्टूबर (जगसीर सिंह)-

संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक रोजगार-उद्गम इंस्टिट्यूट बनने की ओर अग्रसर है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में, रिकॉर्ड संख्या में अत्यधिक प्रतिष्ठित कंपनियो ने स्लाइट के छात्रों का चयन किया और 90% से अधिक छात्रों को अभियांत्रिकी की कई शाखाओं सिलेक्ट किया। वर्तमान में, स्लाइट के छात्रों को लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क किए जाने के कारण और भी भारी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। निस्संदेह इसका श्रेय दूरदर्शी नेतृत्व डॉ. मणि कांत पासवान, निदेशक स्लाइट को जाता है। छात्र क्षमता में उनका दृढ़ विश्वास, बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता और कार्यरत टीम को लगातार प्रोत्साहन अपेक्षित परिणाम प्रदान कर रहा है। डॉ. मणि कांत पासवान के मार्गदर्शन में, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग, छात्रों के प्रशिक्षण, अंतर्निवेश और स्थापन के लिए स्लाइट के साथ सहयोग करने हेतु सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ-साथ सशक्त पूर्व छात्रों तक पहुँचने के लिए एक सहायक रहा है। जुलाई 2026 में वर्तमान सत्र की शुरुआत से, वर्चुसा इसजैक, एलएनटी, जेएसडब्ल्यू, आई ओएलसीपी, वीए टेक डब्ल्यूएबीएजी जैसे कई प्रतिष्ठित संगठनों और अन्य ने छात्रों के प्लेसमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली है या शुरू कर दी है। इंफोसिस, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, ने 10-11 अक्टूबर, 2023 को प्लेसमेंट ड्राइव निर्धारित किया है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्मेंट इस कंपनी में अधिकतम छात्रों को नौकरी दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट और कंप्यूटर डिपार्टमेंट के संयुक्त रूप से, 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित एक सप्ताह की कार्यशाला के रूप में एक व्यापक प्लेसमेंट तैयारी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अभियांत्रिकी और विज्ञान छात्रों ने सप्ताह भर चलने वाली कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों को उनके विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए परिसर के बाहर से और भीतर से कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। यह गहन प्रशिक्षण विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता का नवीनतम प्रमाण है कि प्रत्येक छात्र अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर करियर के अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह से परिष्कृत, कुशल, और तैयार है। व्यापक कार्यशाला को निगम के सर्वोत्तम अभ्यासों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया था और इसका उद्देश्य समग्र कौशल वृद्धि था। सत्रों में मानक पाठ्यक्रम से परे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे, जिनमें व्यक्तित्व विकास और कम्युनिकेशन स्किल, कार्यस्थल नीतिशास्त्र और एम्प्लाईबिलिटी, मनोविज्ञान और मृदु कौशल, विषय तथा साक्षात्कार को कैसे पास करें इस पर विस्तृत मार्गदर्शन शामिल था। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्मेंट ₹छात्रों की सफलता हमारा ध्येय है₹ के विषय पर काम कर रहा है।

पंजाब में 5000 करोड़ की लागत से " रोशन पंजाब " राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट के अभियान का शुभारंभ

करमजीत सिंह रिंटू ने 132 के .वी पावर कालोनी मजीठा रोड में बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण करने का किया शुभारंभ

अमृतसर, 8 अक्टूबर (साहिल बेरी)

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन एवं उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज कर्मजीत सिंह रिंटू ने आज 132 के.वी पावर कालोनी मजीठा रोड में बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण, विस्तार और आधुनिकीकरण करने का शुभारंभ किया। करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय ऊर्जा मंत्री श्री संजीव अरोड़ा जी के सक्रिय सहयोग से, आज 8 अक्टूबर 2025 पंजाब में 5000 करोड़ की लागत से ₹ रोशन पंजाब ₹ राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट के अभियान का शुभारंभ किया गया है। जिसके तहत अमृतसर ज़िले में 307 करोड़ रुपये की लागत से बिजली के बुनियादी ढाँचे के निर्माण, विस्तार और नवीनीकरण का उद्घाटन किया जा रहा है।

करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत, अमृतसर शहर और अमृतसर ज़िले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रमुख कस्बों जैसे बाबा बकाला, जंडियाला गुरु, मजीठा, राजा सांसी, अजनाला और रमदास में बिजली क्षेत्र से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा किअमृतसर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 54 कुल 11 केवी फीडरों से बिजली का भार कम किया जाएगा और नए फीडर बनाए जाएँगे। इन 54 में से 8 फीडरों का कार्य पूरा हो चुका है।

करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि अमृतसर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे ओवरलोडेड वितरण ट्रांसफार्मर हैं। इन ट्रांसफार्मरों को डी-लोड करने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 94 नए ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है और 19 ट्रांसफार्मरों का निर्माण 30/09/2025 तक पूरा हो चुका है।

करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि पुराने फोकल प्वाइंट अमृतसर में औद्योगिक उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा एक नया 66 केवी सबस्टेशन स्वीकृत किया गया है। इस सबस्टेशन का कार्य वर्ष 2026 के दौरान पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए उपर्युक्त कार्यों के पूरा होने से अमृतसर जिले के उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति मिल सकेगी। इस अवसर पर सीनियर डिप्टी में प्रियंका शर्मा,साही सगगर, बलविंदर काला , गुलज़ार सिंह, अनेक सिंह , अंकुश गुप्ता और पीएसपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

विज्ञान परिषद पंचनद द्वारा स्लाइट में बी.वी.एस. आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन

लोंगोवाल, 9 अक्टूबर (जगसीर सिंह)-

संत लोगोंवाल संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर मणि कांत पासवान, तथा प्रोफेसर रवि कांत मिश्रा, डीन (पूर्व छात्र एवं औद्योगिक संबंध) के मार्गदर्शन में बी.वी.एस. (भारतीय विज्ञान सम्मेलन) आउटरीच कार्यक्रम का सफल आयोजन स्लाइट कैंपस में हुआ ,इस कार्यक्रम का समन्वयन प्रोफेसर मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉ. सोम देव भारद्वाज, राष्ट्रीय सचिव, विज्ञान भारती (विभा) मुख्य अतिथि रहे। साथ ही डीन प्रोफेसर कमलेश प्रसाद, प्रोफेसर ए.एस. शाही, प्रोफेसर एम.एम. सिन्हा तथा प्रोफेसर सुरिंदर सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंतर्गत "भारतीय ग्रंथों में निहित विज्ञान का अन्वेषण" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर बी.वी.एस. पुस्तिका का विमोचन विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में किया गया। प्रोफेसर मिश्रा ने विद्यार्थियों को आगामी भारतीय विज्ञान सम्मेलन (बी.वी.एस.) २०२५ में शोध सार प्रस्तुत करने और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, "यह युवा मस्तिष्कों के लिए भारत की वैज्ञानिक विरासत से जुड़ने और उसे समकालीन परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का स्वर्णिम अवसर है।"

बी.वी.एस. २०२५ का आयोजन १६ से १९ दिसंबर २०२५ तक राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में किया जाएगा। इस वर्ष का मुख्य विषय है - "समग्र विकास की भारतीय अवधारणा"।

कार्यक्रम में विज्ञान परिषद पंचनद के प्रतिनिधि श्री अरुण गर्ग ने भी भाग लिया और कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान किया।

नफरती सियासत को पीछे छोड़कर मान सरकार ने विकास, रोज़गार और सांप्रदायिक सद्भावना को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया – धालीवाल

हलका अजनाला में विधायक और पूर्व मंत्री धालीवाल ने 4 .37 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की रखी नींव –

अमृतसर/अजनाला, 9 अक्तूबर (साहिल बेरी)

– आज हलका विधायक और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने हलके में बाढ़ आपदा से एक जनपक्षीय आंदोलनकारी की तरह निपटने के बाद अजनाला हलके में 4 करोड़ 37 लाख रुपये की लागत वाले विकास कार्यों की नींव रखकर विकास का पिटारा खोला।

नींव रखने की रस्म के मौके पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए श्री धालीवाल ने स्पष्ट कहा कि पंजाब में पिछले 75 सालों से कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारें एक ही "उत्तरो काठो में चड़ां" (वोट बैंक की गंदी राजनीति) की नीति पर राज करती रही हैं। इन पार्टियों ने साजिशन मतदाताओं को गुमराह करने के लिए एक-दूसरे पर दोषारोपण की राजनीति को केंद्र बनाया और कथित तौर पर भ्रष्टाचार की गंदगी की बिसात बिछाई।

उन्होंने कहा कि इसी गंदगी को समेटते हुए आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में, भ्रष्टाचार को एक आंदोलन के रूप में लेकर चली। परंपरागत पार्टियों की तरह नफरत और दोषारोपण को राजनीति का केंद्र बनाने की बजाय मान सरकार ने पिछले साढ़े तीन सालों में मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, 56 हज़ार बेरोज़गारों को नौकरी, गोइंदवाल थर्मल प्लांट को निजी हाथों में बेचे जाने से बचाकर फिर सरकारी हाथों में लेना, नशा और गैंगस्टर माफिया का सफाया – जैसे क्षेत्रों में विकास, रोज़गार और सांप्रदायिक सद्भावना को राजनीति का केंद्र बनाकर लोगों को सुख-सुविधाओं और अमन-चैन के साथ जीवन की मुख्यधारा से जोड़ा।

धालीवाल ने समारोह में पंजाब, पंजाबी और पंजाबीअत के हितैषियों से आह्वान किया कि अब उनके जागने का समय आ गया है। ताकि इस कठिन बाढ़ आपदा की घड़ी में पीड़ितों का दुख बांटने की बजाय, बाढ़ पर राजनीति कर अपनी रोटियां सेकने वाली पुरानी सरकारों से जुड़ी पार्टियों का पंजाब और सबके भले के लिए डटकर मुकाबला किया जा सके।

नींव पत्थर रखने के दौरान श्री धालीवाल ने 24.97 लाख रुपये की लागत वाली लिंक सड़क (तेड़ा कलां से मुकाम), 31.2 लाख रुपये की लागत से जैलदार के घर को जाने वाली फिरनी (तेड़ा कलां), 43.33 लाख रुपये की लागत से लिंक सड़क (सारंगदेव गम्मचुक रोड से आबादी सोहन सिंह वाला), 2.7 करोड़ रुपये की लागत से मार्केट कमेटी अजनाला के अधीन पड़ती विभिन्न अनाज मंडियों में स्टील कवर शेड का निर्माण, इसी तरह मंडी अवां में 1.01 करोड़ रुपये की लागत से नए कवर शेड और 29.17 लाख रुपये की लागत से (रमदास–कामलपुरा रोड से कोट गुरबख्श) विकास परियोजनाओं की नींव रखी। इन कार्यक्रमों के दौरान "विकास प्रोजेक्ट ज़िंदाबाद" के नारे गूंजे।

श्री धालीवाल ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन विकास कार्यों को गुणवत्ता और पारदर्शिता के मानकों के अनुसार निर्धारित समय में पूरा किया जाए।

इस मौके पर खुशपाल सिंह धालीवाल, पीए मुख्तार सिंह बलड़वाल, मार्केट कमेटी चेयरमैन बलदेव सिंह बब्बू चेतनपुरा, ओएसडी गुरजंत सिंह सोही, चेयरमैन गुरशरणसिंह जैलदार, सरपंच मनदीप सिंह खोजी तेड़ा, प्रधान भट्टी जसपाल सिंह ढिल्लों, शहरी प्रधान व चेयरमैन अमित औल, तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

कैप्शनः गांव तेड़ा कलां में निर्माणाधीन लिंक सड़क की नींव पत्थर रस्म के दौरान हलका विधायक व पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल, चेयरमैन बब्बू चेतनपुरा, चेयरमैन जैलदार तेड़ा कलां, सरपंच मनदीप सिंह खोजी और अन्य।

जारीकर्ता: एस. प्रशोतम,

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**